लखनऊ

रविवार, 30 अगस्त , 2026

वर्ष : 12 I अंकः 6

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

सच्ची दोस्ती वही होती है, जो सुख के साथ-साथ दुख में भी साथ निभाए।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

नेपाल में बाढ़ से तबाही पर खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा पत्र, मदद की अपील

नई दिल्ली। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने नेपाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और नेपाल को मानवीय मदद भेजने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि वह नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बहुत चिंतित हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1,000 लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लोग भोजन, दवा, आश्रय और अन्य जरूरी मदद के लिए परेशान हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मानवीय और राहत सहायता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बाढ़ के कारण नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में कई भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि बचाव और निकासी के प्रयासों को तेज किया जाए और उनकी सुरक्षित और जल्द भारत वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। विदेश मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि नेपाल में करीब 320 भारतीय नागरिक अभी भी संपर्क में नहीं हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस कठिन समय में हर संभव मदद के लिए तुरंत कदम उठाएगी।

दीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार

गाजियाबाद। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों पर मोदीनगर क्षेत्र में बीते दिनों एक महिला से हुई लूट की वारदात में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, मोदीनगर इलाके में पुलिस टीम नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस को आते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों युवक बाइक को दूसरी दिशा में भगाने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। भागते समय उनकी मोटरसाइकिल खड़ंजे पर पड़ी ईंटों के कारण असंतुलित होकर फिसल गई। इसके बाद, दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर 315 बोर के तमंचे से गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान, पुलिस की एक गोली एक बदमाश के पैर में लग गई। पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में घायल आरोपी ने अपना नाम फारूक बताया, जबकि उसके साथी का नाम कासिम बताया गया है।

'खजाने की लूट' के लिए अखिलेश जनता से मांगें माफी: देवरिया में मुख्यमंत्री योगी का सपा पर तीखा हमला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

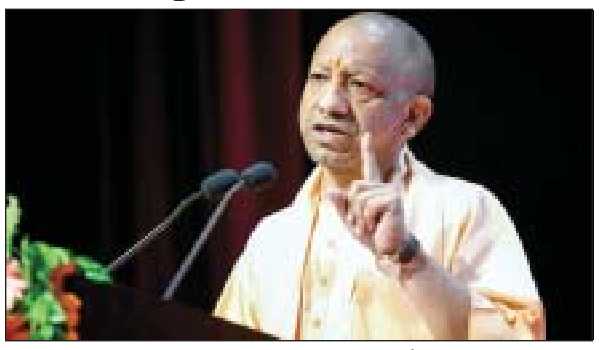

देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया में समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया गया और इसके लिए अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब खराब शासन और असुरक्षा की पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है।

देवरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 305 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 80 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों की प्राथमिकता विकास, समृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना रही है। उन्होंने कानून-व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।

सपा पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा का मतलब लूट और वसूली से है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। योगी ने कहा कि राज्य के खजाने के कथित दुरुपयोग के लिए सपा प्रमुख को जनता से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब विकास और कानून-व्यवस्था के मामले में आगे बढ़ रहा है और इसे अब 'बीमारू' राज्य के तौर पर नहीं देखा जाता।

> उत्तर प्रदेश की छवि में बड़ा बदलाव आया है और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव से अच्छी सरकार बनती है और उसका सीधा असर विकास और रोजगार पर दिखाई देता है।
>
> **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ**

इंसेफेलाइटिस को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस की समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई से 15 नवंबर तक का समय देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और बस्ती समेत कई जिलों के लोगों के लिए चिंता का समय हुआ करता था। योगी ने दावा किया कि करीब 40 वर्षों में इंसेफेलाइटिस से 50 हजार मासूम बच्चों की मौत हुई, लेकिन तत्कालीन सपा और कांग्रेस सरकारों ने समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है।

'माफियाओं का सफाया हो चुका है'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि में बड़ा बदलाव आया है और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव से अच्छी सरकार बनती है और उसका सीधा असर विकास और रोजगार पर दिखाई देता है। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में विकास, सुरक्षा और रोजगार की कमी थी। उनके मुताबिक गरीबों के लिए घर, शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं का भी पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ था। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौर में कई स्कूल नकल के अड्डे बन गए थे।

आदित्य ठाकरे ने जब भरी अदालत में कहा– जज साहब, दिशा सालियन...

मुंबई, एजेंसी। मुंबई हाई कोर्ट में दिशा साल्यान मामले की जांच से जुड़ी याचिका पर अहम सुनवाई हुई। जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस भोसले की बेंच ने मामले से जुड़े कई सवालों पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिशा के शव की स्थिति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल से जुड़े सबूतों पर गंभीर सवाल उठा दिए। लोक अभियोजक शिशिर इहरे ने अदालत को बताया कि अस्पताल में तैयार किए गए पंचनामा में दिशा के शव पर कपड़े नहीं होने का जिक्र था। जिस पर अदालत ने पूछा कि कपड़े किसने हटाए और उससे जुड़े डॉक्टर का बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया। हालांकि सरकारी पक्ष ने साफ किया कि यह घटना स्थल नहीं बल्कि अस्पताल का पंचनामा था। अदालत ने साफ कहा कि वह फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। कोर्ट के मुताबिक इस स्तर पर मर्डर या रेप की पुष्टि करना जरूरी नहीं बल्कि यह देखना महत्वपूर्ण है क्या जांच में संदेह पैदा करने वाली कोई परिस्थिति मौजूद है। सरकारी अभियोजकों ने अस्पताल से ली गई तस्वीरें भी पेश कर दी। तस्वीरों को देखकर अदालत ने चोटों को लेकर सवाल कर दिया। सरकारी पक्ष ने बताया कि ऊंचाई से गिरने के कारण दिशा के चेहरे, खोपड़ी और जबड़े में गंभीर चोटें आई थी। वहीं जांच में यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिलने का दावा किया गया।

दिल्ली-एनसीआर में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप, अस्पतालों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। गौतमबुद्ध नगर में मौसम में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 192 मरीज सामने आ चुके हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। वहीं, जिले में डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब तक 48 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि स्वाइन फ्लू और डेंगू के संदिग्ध मरीजों की पहचान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। गंभीर लक्षण वाले मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में खड़गे के 'शुद्धिकरण' को राहुल गांधी ने बताया अपराध, पूछा– एफआईआर क्यों नहीं?

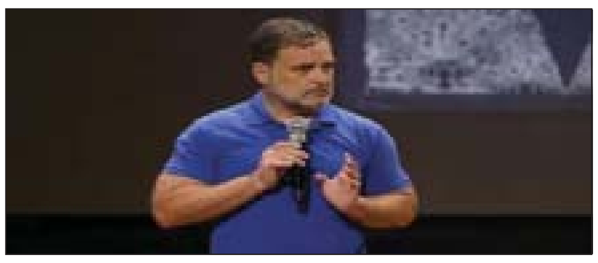

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद एक जगह पर कथित तौर पर शुद्धिकरण की रस्म निभाने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली हुई, जिसे खड़गे ने संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद, खबर है कि श्री राम सेना के सदस्यों ने उसी जगह पर एक शुद्धिकरण हवन किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह रस्म खड़गे को निशाना बनाकर की गई थी क्योंकि वह दलित हैं।

दिल्ली में इंदिरा भवन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह कथित रस्म 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' के तहत आपत्तिजनक है। गांधी ने कहा कि यह काम SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। 'शुद्धिकरण' की रस्म करना एक अपराध है। फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड में जिन्होंने यह शुद्धिकरण की रस्म की, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और इस कथित रस्म पर BJP नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ़ भारत का संविधान है - अंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का संविधान। दूसरी तरफ़ BJP और RSS की विचारधारा है। भारत में अभी जो राजनीति हो रही है, वह इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच है। हज़ारों सालों से इस देश में दलितों पर अत्याचार और हिंसा होती रही है। संविधान ने इसे ग़ैर-क़ानूनी बना दिया है, फिर भी आज भी स्कूलों में दलित बच्चों से शौचालय साफ़ करवाए जाते हैं और फर्श पर झाड़ू-पोछा लगवाया जाता है। ज़रा सोचिए कि इसका आने वाली पीढ़ी के दिमाग़ पर क्या असर पड़ता है: बच्चे अपने कुछ साथियों को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, जबकि झाड़ू लगाने वाले उन साथियों को देखते हैं जिन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता।

उन्होंने कहा कि यही भारत की सच्चाई है। दलितों को गाँव के कुएँ से पानी पीने की इजाज़त नहीं है; उन्हें अपने निजी कुएँ खोदने पड़े क्योंकि उन्हें गाँव के साझा कुएँ का इस्तेमाल करने से रोका गया था। चाय की दुकानों पर आप दो तरह के कप इस्तेमाल होते देखते हैं: एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला काँच का कप जिसे धोया जा सकता है, और दूसरा कागज़ या प्लास्टिक का कप जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है।

पवन खेड़ा का भाजपा पर गंभीर आरोप, दिमागी नक्सल विवाद में युवाओं को हिंसा की धमकी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर देश के युवाओं को हिंसा की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह आरोप BJP कर्नाटक के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लगाया गया है, जिसमें 'दिमागी नक्सल' नाम का एक वीडियो था। 29 अगस्त, 2026 को X पर एक पोस्ट में खेड़ा ने कहा कि आखिरकार उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। BJP ने एक नई सोशल मीडिया टीम बनाई क्योंकि पुरानी टीम की भद्दी भाषा और घटिया हथकंडे काफी नहीं थे। अब वे खुलेआम युवाओं को हिंसा की धमकी देने लगे हैं। आखिरकार उनका असली चेहरा सामने आ रहा है।

खेड़ा ने अपने आरोप को साबित करने के लिए BJP कर्नाटक के पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने भी BJP की पोस्ट की आलोचना की और आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी देश के युवाओं को धमका रही है। 28 अगस्त, 2026 को दास ने X पर लिखा कि सत्ताधारी पार्टी खुलेआम देश के युवाओं को गोली मारकर जान से मारने की धमकी दे रही है! यह सरासर बुराई है। लगता है कि वे अपना आपा खो बैठे हैं! दास ने अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए आगे लिखा कि असल में, यह देखकर थोड़ा दुख होता है कि 'दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी' इतनी ज़्यादा नफ़रत में डूबी हुई है कि उन्हें उस पीढ़ी के 'सामूहिक नरसंहार' की बात करने में कोई बुराई नहीं दिखती, जो सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछने और बस अपने लिए एक बेहतर सिस्टम और उज्ज्वल भविष्य की मांग करने में विश्वास रखती है।

रेल में पेंट्री कार का खाना खाते ही बिगड़ी 30 बच्चों की तबीयत, ट्रेन रोककर कराया इलाज

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली से केरल जा रही मंगला एक्सप्रेस में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन में सफर कर रहे करीब 30 स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी, जिसमें पांच की हालत गंभीर बताई गई। सूचना मिलते ही ट्रेन को खंडवा स्टेशन पर करीब 50 मिनट रोककर सभी बच्चों का इलाज कराया गया।

जानकारी के अनुसार, हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जा रही ट्रेन नंबर 12618 मंगला एक्सप्रेस में त्रिचूर के हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल के 30 छात्र-छात्राएं सवार थे। सभी बच्चे दिल्ली में शैक्षणिक भ्रमण के बाद वापस केरल लौट रहे थे। इसी दौरान चलती ट्रेन में अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी।

भाजपा की 'युवा कनेक्ट' पर रणनीति : नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। 29 अगस्त को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और पूरे देश में युवाओं के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करना था। इस बैठक में हर राज्य से दो-तीन नेता शामिल हुए। बैठक में युवाओं के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों की पहचान करने और युवा पीढ़ी के साथ बातचीत और संवाद को बेहतर बनाने की रणनीतियां तैयार करने पर ध्यान दिया गया। इसमें BJP के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, गुरु प्रकाश पासवान, हेमांग जोशी, योगेंद्र चंदोलिया और राजू बिस्टा शामिल थे। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में मौजूद थीं। इन चर्चाओं का मकसद युवाओं तक बीजेपी की पहुँच और उनसे जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक तालमेल वाला तरीका तैयार करना था। इससे युवाओं की उम्मीदों और भारत के विकास में उनकी भूमिका से जुड़ने पर पार्टी के बड़े फोकस का पता चलता है। इससे पहले, 27 अगस्त को अहमदाबाद में 'फार्मिन्नोवा अवार्ड्स सेरेमनी-2026' में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के भविष्य के लिए युवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास फोकस पर ज़ोर दिया। शाह ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के दौरान मोदी द्वारा बताए गए तीन मुख्य लक्ष्यों का ज़िक्र किया, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न है शाह ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी के लिए एक लक्ष्य तय किया है।

2027 के यूपी चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने दिया PDA का नया फार्मूला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 'PDA' का ज़िक्र किया। PDA यानी पिछड़े (backward), दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार रहे हैं। अखिलेश ने X पर एक पोस्ट में इसे धैर्य, अनुशासन और कार्रवाई (Patience, Discipline, Action) के तौर पर नए सिरे से परिभाषित किया और सामाजिक एकता का आह्वान किया।

X पर शेयर किए गए एक ग्राफ़िक में, अखिलेश ने धैर्य, अनुशासन और कार्रवाई को सफलता की तीन कुंजियाँ बताया। उन्होंने लिखा कि PDA की सकारात्मक राजनीति का सुखद परिणाम यह है कि लोग खुद PDA को अलग-अलग सकारात्मक रूपों में परिभाषित कर रहे हैं। सकारात्मकता से सद्भाव पैदा होता है और सद्भाव से सामाजिक एकता आती है, जो देश को 'प्यार, करुणा और अपनापन' के भाव से जोड़ती है और प्रगति व समृद्धि का नया रास्ता बनाती है।

अखिलेश यादव ने कई मौकों पर PDA आंदोलन का आह्वान किया है और BJP सरकार पर पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 22 अगस्त को एक सभा में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाजवादी विचारधारा और PDA आंदोलन के ज़रिए सामाजिक न्याय स्थापित करने वाली सरकार बनाना है। हालांकि, ऊंची जाति के वोटरों को लुभाने की कोशिश में अखिलेश ने हाल ही में कहा कि PDA में नाराज़ पंडित भी शामिल हैं।

5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने कहा कि जब से BJP लोकसभा चुनाव में PDA से हारी है, वे PDA की तरह-तरह की परिभाषाएं बना रहे हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि PDA का मतलब 'पीड़ित पंडित' है। BJP जितना ज़्यादा दर्द देगी और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ाएगी, PDA उतना ही मज़बूत होगा।

अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार दो हार के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। 2022 में, SP ने 403 में से 111 सीटें जीती थीं, जबकि BJP ने 255 सीटें जीतकर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि, पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने की कोशिश करेगी, जिसमें उसने 80 में से 37 सीटें जीती थीं - जो BJP से चार ज़्यादा थीं।

गलवान में भारत से भिड़ने वाले जनरल के साथ चीन में हो गया खेल, जिनपिंग का एक्शन, पीएलए में भूचाल

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन ने जनरल झाओ ज़ोंगकी को देश की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है। झाओ ने 2017 के डोकलाम गतिरोध और 2020 में भारत के साथ गलवान घाटी झड़प के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभाली थी। बाद में यह खबर आई थी कि झाओ ने 'भारत को सबक सिखाने' के लिए गलवान ऑपरेशन को मंज़ूरी दी थी। PLA का वेस्टर्न कमांड ही तिब्बत और शिनजियांग में, और भारत के साथ चीन की सीमा के बड़े हिस्से पर चीनी सैन्य अभियानों को नियंत्रित करता है। झाओ की 'चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस' (CPPCC) की सदस्यता छीन ली गई और उन्हें दो अन्य पदों से भी हटा दिया गया। बीजिंग ने न तो झाओ को हटाने की वजह बताई और न ही उनके खिलाफ किसी जांच का ऐलान किया। झाओ को हटाए जाने के बाद ऐसी अटकलें तेज़ हो गई हैं कि वह PLA में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लंबे समय से चल रहे बड़े पैमाने पर सफाए की चपेट में आने वाले सबसे नए सीनियर मिलिट्री अधिकारी हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झाओ को तब हटाया गया जब शी के चीन ने अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन' के शक में जांच के बाद दो अन्य सीनियर जनरलों झांग यूक्सिया और लियू झेनली को स्टेट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटा दिया। शी के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान (जिसे एक्सपर्ट्स ने 'सफाया' या पर्ज कहा है) के तहत 2012 से अब तक कई सीनियर अधिकारियों की जांच हुई है।

बरेली में कैसे बेकाबू हो गई महिलाओं की भीड़? एक की मौत, कई घायल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। बरेली क्लब में मेयर उमेश गौतम की ओर से आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में गुरुवार को भारी भीड़ के चलते अफरा-तफरी मच गई। गर्मी और उमस के बीच धक्का-मुक्की में कई महिलाएं बेहोश और घायल हो गईं। एक महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मधु सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया है।

कैंट थाना क्षेत्र स्थित बरेली क्लब में बीजेपी मेयर डॉ। उमेश गौतम की ओर से सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। आयोजकों की ओर से करीब 20 हजार से अधिक महिलाओं के पहुंचने का दावा किया गया। सुबह करीब 10 बजे से ही महिलाओं का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था।

करीब 11 बजे तक मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई। भीषण गर्मी और उमस के बीच लगातार बढ़ती भीड़ के कारण कुछ देर बाद स्थिति बिगड़ने लगी।

धक्का-मुक्की में कई महिलाएं बेहोश

कार्यक्रम में महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए पहले से कूपन बांटे गए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों और बुजुर्ग परिजनों के साथ पहुंची थीं। भीड़ बढ़ने के बाद मैदान में जगह कम पड़ गई और महिलाएं बैरिकेडिंग पार कर मंच की ओर जाने लगीं। इसी दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कई महिलाएं गिर गईं। कुछ गर्मी व भीड़ के दबाव के कारण बेहोश हो गईं। मौके पर मौजूद एंबुलेंस की मदद से बेहोश और घायल महिलाओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया।

महिला की हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत

कार्यक्रम के दौरान एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मधु सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गर्मी और उमस के कारण मधु सिंह की हालत बिगड़ी थी। हालांकि, उनकी मौत की पूरी वजह पोस्टमार्टम या चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस कार्रवाई को लेकर परिजनों ने फिलहाल इनकार किया है।

मंच पर बढ़ी भीड़, बेटे को गेट पर भेजा

हालात बिगड़ते देख मेयर डॉ। उमेश गौतम ने भीड़ को अलग-अलग जगह बांटने की कोशिश की। बताया गया कि उन्होंने अपने बेटे पार्थ गौतम को मुख्य गेट की ओर भेजा, ताकि वहां भी महिलाओं से राखी बंधवाई जा सके। इसके बावजूद मंच के आसपास भीड़ का दबाव कम नहीं हुआ। कई महिलाएं मंच की तरफ बढ़ने लगीं। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में आयोजकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

करीब पांच मिनट तक भीड़ में दब गई थी बच्ची

कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने भीड़ की स्थिति को लेकर अपनी आपबीती बताई। उनका कहना था कि भीड़ में एक बच्ची दब गई थी। करीब पांच मिनट तक दबे रहने के बाद उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्ची के हाथ-पैर में चोट आई। एक अन्य महिला ने बताया कि भीड़ के बीच धक्का-मुक्की इतनी ज्यादा थी कि लोग एक-दूसरे पर गिर रहे थे। उसका कहना था कि महिलाओं के साथ बच्चों को भी काफी परेशानी हुई और कई लोग घायल हो गए।

जान बचाकर बाहर निकलना पड़ा

भुता क्षेत्र से कार्यक्रम में पहुंची एक महिला ने बताया कि जब वह मंच की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी तो भीड़ में किसी ने उनका हाथ खींच लिया। धक्का-मुक्की के दौरान उनकी चप्पल और पैरों में पहनी बिछिया तक निकलकर गिर गई। महिला के मुताबिक, भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें किसी तरह अपनी जान बचाकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलना पड़ा। वहीं, बच्चे को गोद में लेकर पहुंची एक महिला ने बताया कि पीछे से भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। दबाव बढ़ने पर बच्चा हाथ से नीचे गिरते-गिरते बचा। उनकी सास को भी भीड़ ने धक्का दे दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गईं।

बच्चे भीड़ में बिछड़े, लगातार हुआ अनाउंसमेंट

भारी भीड़ के बीच कुछ बच्चों के अपने परिजनों से बिछड़ने की बात भी सामने आई। कार्यक्रम स्थल पर लाउडस्पीकर के जरिए लगातार बच्चों और उनके परिजनों के बारे में अनाउंसमेंट कराया गया। मैदान में कई जगह टूटी चूड़ियां, चप्पल और अन्य सामान भी बिखरा नजर आया। इससे कार्यक्रम के दौरान बने हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उपहार बांटने के दौरान भी बढ़ा दबाव

कार्यक्रम में महिलाओं को उपहार भी बांटे जा रहे थे। उपहार लेने के दौरान भी भीड़ का दबाव और बढ़ गया। महिलाओं में उपहार लेने की होड़ के बीच कई जगह धक्का-मुक्की हुई। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि इसी दौरान उनके मोबाइल फोन, पर्स में रखी नकदी और गले की चेन चोरी हो गई। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस की ओर से अभी पुष्टि नहीं की गई है।

कार्यक्रम की व्यवस्था पर उठे सवाल

कार्यक्रम में शामिल नीलिमा समेत कई महिलाओं ने आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया गया था तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे। महिलाओं ने गर्मी और उमस के बीच पानी, सुरक्षित रास्ते और भीड़ नियंत्रण की बेहतर व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि त्योहार के कार्यक्रम में परिवार और बच्चों के साथ पहुंचना मुश्किल हो गया। घटना के बाद कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल घायल महिलाओं को किस-किस अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, कार्यक्रम में अव्यवस्था और एक महिला की मौत के मामले में मेयर डॉ। उमेश गौतम की ओर से भी बयान नहीं आया है।

नर्सिंग छात्रा की मौत में प्रधानाचार्य-वार्डन पर एफआईआर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अमेठी/सुलतानपुर। मुंशीगंज स्थित इंदिरा गांधी स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जीएनएम तृतीय वर्ष की छात्रा दीप्ति यादव की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ.रमेश और वार्डन नेहा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतका की मां सुनीता यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला गरमा गया है। परिजनों ने मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल की परिस्थितियां संदिग्ध थीं और उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना शव के संबंध में जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। परिजनों ने कॉलेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका की मां सुनीता यादव ने दो टूक कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती,बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार के इस रुख से पुलिस-प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। तहरीर के मुताबिक घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे दीप्ति की परिजनों से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद कॉलेज से उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। परिजन कॉलेज पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटनाक्रम को लेकर परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रधानाचार्य और वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

तिरहुत बाजार में 'स्वच्छता मिशन' की खुली पोल, कूड़े के ढेर में दम तोड़ती सफाई व्यवस्था

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुल्तानपुर। बल्दीराय विकासखंड की ग्रामसभा तिरहुत बाजार में स्वच्छता व्यवस्था की बदहाली ने ग्रामीण स्वच्छता मिशन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बाजार में दो प्रमुख मंदिरों के आसपास और आबादी के बीच लंबे समय से कूड़े-कचरे का ढेर लगे होने की शिकायत अब जिला प्रशासन तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता मृत्युंजय सिंह सिसोदिया ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मौके की सफाई कराने के साथ जिम्मेदारों की भूमिका की जांच की मांग की है।

जिस स्थान पर कचरा जमा होने की बात कही जा रही है, उसके आसपास दो मंदिरों के अलावा गांव और बाजार की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में खुले में पड़ा, सड़ा-गला कचरा, गंदगी और गंदे पानी का जमाव स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बरसात के मौसम में जलभराव के साथ स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। यह महज गंदगी का मामला नहीं है। आबादी के बीच लगातार कचरा पड़ा रहना मच्छरों और अन्य कीटों के पनपने की परिस्थितियां पैदा कर सकता है, जिससे संक्रामक घातक रोगों का खतरा बढ़ सकता है। सवाल यह है कि जब स्वच्छता व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, तो फिर तिरहुत बाजार में सफाई क्यों नहीं दिखाई दे रही?

ग्रामसभा में तैनात सफाईकर्मी नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों की सफाई करने के बजाय, कहां कार्य करते हैं ? जब गांव के कचरे, नाली डम्प हैं तो कार्य कहां हुआ ? गांव वालों के मुताबिक सफाईकर्मी आते ही नही हैं गांव में। ग्रामसभा में सफाई व्यवस्था की जाँच आवश्यक जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते, मनमानी सफाई कर्मी ग्रामसभा में सफाई कार्य व्यवस्था के प्रति शून्य हैं। जिसका जीत जगस्त उदाहरण प्रत्यक्ष है। जिसकी जांच और कार्यवाई भी आवश्यक है।

जांच हुई तो खुल सकते हैं कई राज!

मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सफाईकर्मियों की वास्तविक तैनाती, उपस्थिति पंजिका, कार्यस्थल, सफाई व्यवस्था पर होने वाले खर्च और मौके की स्थिति इन सभी का मिलान किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि स्वच्छता व्यवस्था केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित है या वास्तव में गांव-बाजार में इसका लाभ पहुंच रहा है। यदि जांच में सरकारी सफाईकर्मियों को निजी कार्यों में लगाए जाने के आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

अब 'सफाई' नहीं, जवाबदेही की दरकार

तिरहुत बाजार में जमा कूड़ा केवल एक स्थान की गंदगी नहीं, बल्कि संपुर्ण विकासखण्ड में, पंचायत स्तर की स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल है। सफाई कर्मियों की मनमानी कई ग्रामसभाओं में आसानी से देखी जा सकती है। तिरहुत में ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके का स्थलीय निरीक्षण कराए, सफाई व्यवस्था की जांच करे और दोषी पाए जाने वालों की जवाबदेही तय करे। अब देखना यह है कि शिकायत के बाद प्रशासन सिर्फ कूड़ा हटवाकर मामला शांत करता है।

स्वाइन फ्लू से जंग लडने के लिए मेडिकल कॉलेज ने की तैयारी

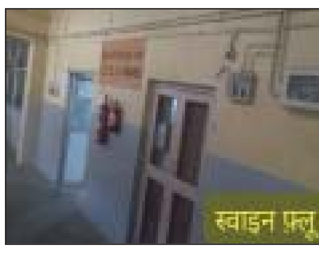

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। स्वाइन फ्लू से दो-दो हांथ करने के लिए मेडिकल कॉलेज पूरी तरह एलर्ट मोड पर है। प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डां.प्रियांक वर्मा ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अभी तक पुरानी बिल्डिंग के आईसीयू वार्ड में 10 बेड सुरक्षित करने के साथ ही आवश्यक औषधि तथा डॉक्टरों की टीम को एलर्ट मोड पर रखने की बात कही है, साथ ही प्राचार्य डां.प्रियांक वर्मा ने बताया की अतिशीघ्र आठ बेड स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए और बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, वही मुख्य चिकित्साधिक्षक डां.एसी गुप्ता ने बताया की यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस फूलने की शिकायत हो तो फौरन नजदीकी सरकारी अस्पताल जाए, साथ ही ऐसे मरीजों को भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचना चाहिए, मरीज व आम लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए तथा हांथ मिलाने से बचना चाहिए सीएमएस डां.अविनाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि स्वाइन फ्लू में भी उतना ही एहतियात बरतना होगा जितना कोरोना के समय किया गया था। डां.अविनाश चंद्र गुप्ता ने बताया की घबराए नहीं अफवाहों पर ध्यान न दे,यदि किसी को खांसी, बुखार, सर्दी या सांस फूलने की शिकायत है तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए डाक्टर की सलाह ले यदि स्वाइन फ्लू के लक्षण है तो जांच व ईलाज करवाएं।

रक्षाबंधन पर घर लौटे युवक को बदमाशों ने मारी तीन गोलियां

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। रक्षाबंधन पर परिवार के साथ त्योहार मनाने मध्य प्रदेश से घर लौटे 40 वर्षीय युवक विपिन सिंह को शुक्रवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। ढेमा चौराहे पर घर के बाहर हुई फायरिंग में विपिन के बाएं सीने में तीन गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

घटना शुक्रवार रात करीब 11.45 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार, विपिन घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान तीन बाइक सवार हमलावर पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से विपिन जमीन पर गिर पड़े। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी मोतिगरपुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। मुड़हा निवासी शिवम सिंह और इंद्रसेन सिंह के परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद बताया जा रहा है। घायल विपिन इंद्रसेन सिंह के पुत्र हैं। विपिन के चाचा दान बहादुर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने शिवम सिंह और दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

'ईंधन आपूर्ति बंद या एयर फ्लेम सिस्टम फेल?', विशेषज्ञ लगा रहे हैं कयास, नहीं होता पैराशूट

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर में इटली की टेक्नाम कंपनी का टेक्नो पी2006टी विमान गुरुवार को हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। यह विमान दुनिया का सबसे हल्का और किफायती दो इंजन वाला है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक पायलटों के प्रशिक्षण और निजी यात्राओं के लिए किया जाता है। गर्ग एविएशन में इस विमान से प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

इसमें पैराशूट नहीं होता है। वहीं, एविएशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि डीजीसीए की जांच रिपोर्ट के बाद ही हादसे की तस्वीर साफ होगी। हालांकि, इंजन में ईंधन आपूर्ति बंद होने या एयर फ्लेम कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी हादसा की वजह हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, टेक्नो पी2006टी में रोटैक्स 912 सीरीज के दो लिक्विड-कूल्ड इंजन लगे होते हैं।

तब विमान की कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है

इस स्थिति में विमान हादसे के दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला यह कि दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति बाधित हो गई। इंजन बंद होने से विमान हवा में ही रुक गया और क्रैश होकर नीचे आ गिरा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि विमान के एयर फ्लेम सिस्टम में कोई तकनीक कमी आ गई। इस सिस्टम के काम न करने से विमान की कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है।

सबसे कम ईंधन खपत करता है

प्रत्येक इंजन 100 हॉर्स पावर की शक्ति का होता है। यह विमान अपनी श्रेणी में सबसे कम ईंधन खपत करता है। इसके दोनों इंजन मिलकर प्रति घंटा 34 से 38 लीटर ईंधन खाते हैं। यह कई एकल इंजन विमानों के बराबर है। यह पारंपरिक एविएशन ईंधन के साथ-साथ सामान्य कारों में इस्तेमाल होने वाले सीसा रहित पेट्रोल पर भी उड़ सकता है।

उड़ान भार 1,180 से 1,230 किलोग्राम के बीच

इससे इसकी परिचालन लागत बेहद कम हो जाती है। यह दुनिया का सबसे हल्का प्रमाणित दो इंजन वाला नागरिक विमान है। इसका अधिकतम उड़ान भार 1,180 से 1,230 किलोग्राम के बीच होता है। विमान में एक पायलट और तीन यात्रियों सहित कुल चार सीटें होती हैं। इसके ऊपरी पंख डिजाइन से पायलट और यात्रियों को नीचे और बाहर का स्पष्ट दृश्य मिलता है।

सिकुड़ने वाले लैंडिंग गियर भी लगे हैं

यह हवा में करीब 260 से 270 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज गति से उड़ सकता है। एक बार पूरा ईंधन भरने पर यह लगभग 1,200 से 1,740 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें सिकुड़ने वाले लैंडिंग गियर भी लगे हैं। यह उड़ान के दौरान हवा के अवरोध को कम करते हैं और गति बढ़ाते हैं। इसमें आधुनिक गार्मिन जी1000एनएक्सआई ग्लास कॉकपिट और ऑटोपायलट प्रणाली भी लगी होती है।

20 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया

यह डिजिटल स्क्रीन पर उड़ान और दिशा-निर्देशन की सारी सटीक जानकारी देता है। दो इंजन होने के कारण यह विमान अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। यदि उड़ान के दौरान एक इंजन खराब भी हो जाए तो यह विमान दूसरे इंजन पर भी सुरक्षित रूप से उड़ने और उतरने में सक्षम है। यह विशेषता इसे एकल इंजन विमानों से बेहतर बनाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया।

यूपी में हरियाणवी सिंगर हत्याकांड: रडार पर इन छह गैंग का नेटवर्क, दिल्ली-हरियाणा से पश्चिमी यूपी तक कड़ियां

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में गोगी गैंग के हत्या की जिम्मेदारी लेने के बावजूद पुलिस को जांच में कई आपराधिक गिरोहों के गुर्गों के आपसी संपर्क के अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या अंकित की हत्या के पीछे अकेले गोगी गैंग था या कई गैंगों के गुर्गों ने मिलकर साजिश रची।

जांच में जितेंद्र गोगी, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़ और नीरज बवाना से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो डालने वालों के संपर्क, बातचीत और लोकेशन की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार सोशल मीडिया पर गैंग से संबंधित वीडियो और पोस्ट डालने वालों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में गोगी के अलावा नीरज बवाना और अन्य गैंगों से जुड़े सदस्यों के आपसी संपर्क की जानकारी भी सामने आई है। सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर एक संदिग्ध की लोकेशन रोहतक और दूसरे की दिल्ली में मिलने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ते हुए यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश किसने रची और वारदात को अंजाम देने वालों तक निर्देश किस माध्यम से पहुंचे। एसपी का कहना है कि जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही हत्याकांड में शामिल आरोपियों तथा पूरी साजिश का खुलासा कर दिया जाएगा।

गोगी गैंग: जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट से शुरू हुई जांच

अंकित की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट वायरल हुई। इसके बाद पुलिस ने पोस्ट डालने वाले और उसके संपर्कों की पड़ताल शुरू की। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पोस्ट वास्तव में गैंग से जुड़े व्यक्ति ने डाली है या किसी ने जांच को भटकाने के लिए गोगी गैंग का नाम इस्तेमाल किया।

काला जठेड़ी: दिल्ली-हरियाणा से पश्चिमी यूपी तक कड़ियां

काला जठेड़ी का नाम दिल्ली-हरियाणा के साथ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा रहा है। उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से भी जोड़ा जाता रहा है। पुलिस अंकित हत्याकांड में जठेड़ी नेटवर्क से जुड़े संभावित संपर्कों की भी जांच कर रही है।

लॉरेंस-संपत नेहरा नेटवर्क की दूसरी कड़ी

लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में संपत नेहरा का नाम प्रमुखता से सामने आता रहा है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े किसी व्यक्ति का अंकित हत्याकांड के आरोपियों से कोई संपर्क था या नहीं।

गोल्डी बराड़ : डिजिटल नेटवर्क पर नजर

गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी बताया जाता रहा है। पुलिस अंकित हत्याकांड में सामने आई सोशल मीडिया गतिविधियों और डिजिटल संपर्कों की जांच के दौरान इस नेटवर्क की कड़ियां भी खंगाल रही है।

नीरज बवाना : गोगी का पुराना विरोधी गुट

नीरज बवाना का नाम दिल्ली के बड़े आपराधिक नेटवर्क में रहा है। गोगी गैंग के साथ उसकी पुरानी गैंगवार का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे में पुलिस दोनों नेटवर्क के मौजूदा संपर्कों और गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है।

अंकित हमारे दुश्मनों से मिला था... कर दी हत्या

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली है। गोगी गैंग से जुड़े भोलू शाहपुरिया के नाम से इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट में लिखा गया है कि अंकित उसके दुश्मनों से मिला हुआ था। इसलिए उसकी हत्या की गई। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। वहीं, बृहस्पतिवार को अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने हत्यारोपियों के एनकाउंटर की मांग की है।

पोस्ट में भोलू ने यह भी लिखा है कि अंकित गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के बाद टिल्लू गैंग के समर्थन में गाना बनाकर गोगी के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था। यही नहीं अंकित उनके दुश्मनों के आपराधिक कामों में साथ देता था। पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में लिखा गया है कि यह तो अभी शुरुआत है। सभी का नंबर आएगा।

एसपी एनपी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हत्यारोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अंकित बालियान की बुधवार की शाम जिम के बाहर गाड़ी में बैठने के दौरान बाइक सवार चार हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। अंकित मूलरूप से शामली के गांव बंतीखेड़ा के रहने वाले थे।

छात्र राजनीति से पनपी दुश्मनी

शामली के गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस ने दिल्ली-हरियाणा में लंबे समय से चल रही गैंगवार की कड़ियां खंगालनी शुरू कर दी हैं। गोगी और टिल्लू गैंग की दुश्मनी की शुरुआत कॉलेज की छात्र राजनीति से हुई थी। वर्चस्व की लड़ाई धीरे-धीरे व्यक्तिगत रंजिश और फिर संगठित अपराध में बदल गई।

जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री योगी ने, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और शीघ्रता के साथ संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना भेदभाव प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को ध्यान से सुना। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और लोगों को भरोसा दिलाया कि हर पीड़ित की समस्या का पारदर्शी समाधान कराया जाएगा।जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों के उच्च स्तरीय उपचार का अनुमान शीघ्र तैयार कराया जाए, ताकि सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर भू-माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। वहीं पारिवारिक विवादों के मामलों में उन्होंने संबंधित पक्षों के बीच पहले संवाद स्थापित कर समाधान की पहल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की। उन्होंने गायों और गोवंश को स्नेहपूर्वक पूड़ी और गुड़ खिलाया। इससे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया।

योगी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे प्रदेश की समीक्षा, बाढ़-जलभराव से लेकर कानून व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति पर होगी चर्चा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम सात बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार बैठक में राजस्व, जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों, राजस्व विभाग के लंबित वादों, जलभराव, बाढ़, आगामी त्योहारों, विद्युत आपूर्ति और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक क्षेत्र, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी शामिल होंगे।इसके अलावा ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, पंचायती राज, परिवहन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सिंचाई, लघु सिंचाई, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल निगम, पशुपालन सहित संबंधित विभागों के मंडल एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में प्रतिभाग करेंगे।मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में विशेष रूप से बाढ़ और जलभराव की स्थिति, राजस्व मामलों के लंबित वादों, जनता की शिकायतों के निस्तारण तथा आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में पूरी तैयारी के साथ शामिल होने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि बाढ़ एवं राजस्व वादों से संबंधित सभी अधिकारी और वरिष्ठ कार्मिक भी बैठक में उपस्थित रहें। सभी प्रतिभागी अधिकारियों को बैठक शुरू होने से 15 मिनट पहले अपना स्थान ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश से बढ़ेगा रोजगार और किसानों की आय : केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, किसानों की आय बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि नीति के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। निवेश प्रस्तावों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास, कृषि मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्यों को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है।उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक है कि प्रदेश के नवयुवाओं का रुझान पारंपरिक एवं पुश्तैनी व्यवसायों से आगे बढ़कर आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। महिला उद्यमी भी इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर निवेश कर रही हैं, जो उद्यमिता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सुरक्षित, अनुकूल और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीणा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश का रुझान तेजी से बढ़ा है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 3.50 हजार इकाइयां स्थापित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से 579 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनकी औसत लागत करीब चार करोड़ रुपये प्रति इकाई है। रामपुर और बरेली में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के हब, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में बिस्कुट एवं नमकीन के हब, बाराबंकी में रेडी-टू-ईट फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र, अमेठी में पशु आहार उत्पादन तथा उन्नाव में मुर्गी दाना उत्पादन और देवरिया में मछली के फ्लोटिंग दाना उत्पादन की इकाइयां स्थापित की गई हैं।इन प्रयासों से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। विदेशों में कार्यरत रहे उत्तर प्रदेश के करीब 200 युवाओं ने वापस आकर प्रदेश में अपने उद्यम स्थापित किए हैं।

क्षेत्रीय क्षमता के अनुरूप औद्योगिक विकास से बदल रहा उत्तर प्रदेश का आर्थिक भूगोल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विशालता उसकी पहचान के साथ-साथ विकास नीति की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक आवश्यकताएं पूर्वांचल से अलग हैं, जबकि बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियां मध्य उत्तर प्रदेश से भिन्न हैं। ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक विकास को किसी एक महानगर या औद्योगिक पट्टी तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक अंचल की स्थानीय क्षमता और आर्थिक विशेषताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित हो रहे औद्योगिक पार्क और क्लस्टर इसी संतुलित औद्योगिकीकरण की व्यापक परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं।प्रदेश की कृषि शक्ति को उद्योग से जोड़ने के लिए बरेली में मेगा फूड पार्क महत्वपूर्ण पहल है। कृषि उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होने से किसानों को बेहतर बाजार, उद्योगों को कच्चा माल और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इससे कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन का बड़ा हिस्सा प्रदेश के भीतर ही रहने की संभावना है।मध्य उत्तर प्रदेश में उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी लखनऊ-कानपुर आर्थिक क्षेत्र की संभावनाओं को नया आधार प्रदान कर रही है। दो बड़े शहरी एवं आर्थिक केंद्रों के बीच स्थित होने के कारण यह क्षेत्र उद्योग, आवास और सेवा क्षेत्र के विकास की व्यापक संभावनाएं रखता है।पूर्वांचल में गोरखपुर के गारमेंट पार्क और प्लास्टिक पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

• संक्षेप •

रक्षाबंधन पर लिफाफा वितरण को लेकर ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले- 'राखी घोटाला' करके बैठ गए?

लखनऊ। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को लिफाफा वितरण को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को 11 हजार रुपये देने के नाम पर बुलाया गया, लेकिन उन्हें 1100 रुपये का लिफाफा थमा दिया गया।ओपी राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि 11 हजार रुपये देने की बात कही गई थी तो महिलाओं को केवल 1100 रुपये ही क्यों दिए गए? उन्होंने तंज कसते हुए अखिलेश यादव से पूछा कि "लिफाफे से बाकी 9900 रुपये कहां गायब हो गए?"राजभर ने आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि महिलाओं को 11 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी तो पूरी राशि दी जानी चाहिए थी। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि "अखिलेश जी, कुछ नहीं मिला तो 'राखी घोटाला' करके बैठ गए?"उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए अपने राजनीतिक अंदाज में कहा कि पार्टी के भीतर मौजूद 'विभीषणों' से जल्द छुटकारा पा लीजिए, वरना ये आपकी लंका लगा देंगे।

H1N1 और सीजनल फ्लू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा, अस्पतालों में दवाओं और बेड की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में H1N1 और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से फ्लू की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में H1N1 और सीजनल फ्लू से संबंधित दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अस्पतालों में आवश्यकतानुसार बेड की उपलब्धता बनाए रखने तथा मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।उपमुख्यमंत्री ने फ्लू की जांच व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी होगी। अस्पतालों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों को 7 सितंबर तक ईएसएस पोर्टल पर विद्युत संयोजन का विवरण अपडेट करना अनिवार्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने सभी कार्यरत कार्मिकों के विभागीय विद्युत संयोजन (एलएमवी-10) से संबंधित विवरण को ईएसएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन कराने के निर्देश दिए हैं। कारपोरेशन के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) डॉ. जॉन मथाई की ओर से 25 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों के सभी कार्मिकों के एलएमवी-10 विद्युत संयोजनों का प्रमाणिक एवं अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने तथा संबंधित अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए ईआरपी के ईएसएस (कर्मचारी स्वसेवा) पोर्टल पर एलएमवी-10 विद्युत संयोजन से संबंधित विवरण दर्ज करने की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।कारपोरेशन ने पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम तथा केस्को के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों को ईएसएस पोर्टल पर लॉग-इन कर अपने विद्युत संयोजन का विवरण 7 सितंबर 2026 तक पूर्ण, सही और अद्यतन रूप में दर्ज करने के लिए निर्देशित करें।

जन्माष्टमी पर बसों के सुचारु संचालन को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए सख्त निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के व्यवस्थित एवं सुदृढ़ संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने चालक-परिचालकों और बस अड्डों पर तैनात कर्मचारियों को यात्रियों के साथ मृदुल एवं शिष्ट व्यवहार करने के निर्देश दिए।परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम की सभी बसों का निर्धारित 31 एवं 13 बिंदुओं के मानक के अनुसार भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण तत्काल कराया जाए। परीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का तत्काल निराकरण और आवश्यक मरम्मत कराई जाए तथा फिटनेस की स्थिति में ही बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बसों को हमेशा ऑन रोड स्थिति में रखते हुए शत-प्रतिशत संचालन के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि बस यात्रियों को परिवहन सुविधा के साथ बस अड्डों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल और साफ-सुथरे सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बस स्टेशनों के शौचालयों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ चूने का छिड़काव भी सुनिश्चित किया जाए। दयाशंकर सिंह ने बसों को मार्ग पर भेजने से पहले उनकी साफ-सफाई और फिटनेस की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी बस के शीशे टूटे हुए अथवा सीट फटी हुई नहीं होनी चाहिए। सभी बसें यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में ही संचालित की जाएं।परिवहन मंत्री ने चालकों एवं परिचालकों को यात्रियों के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

अधिवक्ताओं के चैंबरों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध

लखनऊ। प्रशासन द्वारा 30 अगस्त 2026 को अधिवक्ताओं के चैंबरों के ध्वस्तीकरण की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रस्तावित कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 4 अगस्त 2026 को सीआरपीआईएल संख्या 4/2026 में दिए गए निर्देशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के "इन रीः मनोज तिबरेवाल" मामले में जारी बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।अधिवक्ताओं के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त के आदेश में शेष 58 चैंबरों के संबंध में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की थी। इसके तहत एक सप्ताह के भीतर नए नोटिस जारी किए जाने, प्राप्त उत्तरों पर विचार कर संबंधित पक्षों को निर्णय से अवगत कराने तथा इसके बाद ध्वस्तीकरण के संबंध में कार्रवाई से पहले 10 दिन का समय दिए जाने के निर्देश थे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

जिलाबदर अपराधी सनी सिंह उर्फ सत्या गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ के थाना माल पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम उत्तरी ने जिलाबदर अपराधी सनी सिंह उर्फ सत्या को जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से ग्राम सैमसी क्षेत्र में गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की है।पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को थाना माल पुलिस और स्वाट टीम उत्तरी को मुखबिर से सूचना मिली कि जिलाबदर अपराधी सनी सिंह उर्फ सत्या थाना माल क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सनी सिंह उर्फ सत्या पुत्र महेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू, निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना माल, लखनऊ, उम्र करीब 31 वर्ष को ग्राम सैमसी से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक सनी सिंह को संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), कमिश्नरेट लखनऊ के वाद संख्या 92(62)/2026 में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत पारित आदेश के क्रम में 21 अगस्त 2026 से छह माह के लिए जिलाबदर किया गया था। इसके बावजूद उसने जिलाबदर अवधि पूरी होने से पहले लखनऊ जिले की सीमा में प्रवेश किया, जिसे जिलाबदर आदेश का उल्लंघन माना गया।इस संबंध में थाना माल में मु0अ0सं0 185/2026, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें थाना माल में वर्ष 2026 के मुकदमे संख्या 165 और 71, वर्ष 2025 का मुकदमा संख्या 79, थाना अलीगंज में वर्ष 2024 का मुकदमा संख्या 83, थाना माल में वर्ष 2023 का मुकदमा संख्या 86, वर्ष 2020 का मुकदमा संख्या 230, वर्ष 2017 का मुकदमा संख्या 36 तथा वर्ष 2016 का मुकदमा संख्या 39-ए शामिल हैं।

मोहनलालगंज पुलिस ने सात दिन में लापता दो नाबालिग बालकों को पंजाब से सकुशल बरामद किया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ के थाना मोहनलालगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आश्रयालय से लापता हुए दो नाबालिग बालकों को सात दिन के भीतर पंजाब से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दोनों बालकों का पता लगाया और उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी।पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त 2026 को डॉन बॉस्को आश्रयालय के निदेशक बिमल क्रेकेटा की ओर से सूचना दी गई कि आश्रयालय में रह रहे 14 वर्ष और 13 वर्ष के दो नाबालिग बालक बिना बताए कहीं चले गए हैं और वापस नहीं लौटे। खोजबीन के बाद थाना मोहनलालगंज में मुकदमा संख्या 311/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।घटना के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज राम बाबू सिंह ने दो पुलिस टीमों का गठन किया। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के साथ तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में दोनों बालकों के पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (सासनगर) जनपद के खरड़ क्षेत्र में अपनी बुआ के घर पर होने की जानकारी मिली।इसके बाद मोहनलालगंज पुलिस टीम पंजाब के थाना सिटी खरड़ पहुंची और स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से दोनों बालकों की बुआ के घर पहुंची। वहां दोनों नाबालिग सकुशल मौजूद मिले। पुलिस ने बुआ से पूछताछ करने के साथ ही मोहनलालगंज थाने में दर्ज मुकदमे की जानकारी दी और दोनों बालकों को सकुशल बरामद कर लिया।पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें डॉन बॉस्को आश्रयालय में अच्छा नहीं लग रहा था। इसी कारण उन्होंने 18 अगस्त की रात मौका देखकर आश्रयालय से निकलने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मोहम्मद मुश्ताक के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज राम बाबू सिंह ने किया।

बीबीएयू के 11वें दीक्षांत समारोह में राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों से कहा- बड़े लक्ष्य के लिए मन बड़ा रखें

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में शनिवार को 11वें दीक्षांत समारोह-2026 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023, 2024, 2025 एवं 2026 के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार, बीबीएयू के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल तथा परीक्षा नियंत्रक प्रो. विक्रम सिंह यादव मंच पर मौजूद रहे।समारोह का शुभारंभ अतिथियों एवं कुलपति द्वारा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद शैक्षणिक शोभायात्रा, दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत का सामूहिक गायन हुआ। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीति चौधरी ने किया।मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता" का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन को बड़ा रखना आवश्यक है। व्यापक सोच और सकारात्मकता से व्यक्ति सुख एवं संतुष्टि की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और चिंतन अत्यंत समृद्ध रहा है तथा संत-महात्माओं ने सदियों पहले जिन जीवन-मूल्यों की बात की थी, आज पूरी दुनिया उन्हें अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत जो बोलता है, दुनिया उसे ध्यान से सुनती है।राजनाथ सिंह ने कहा कि बीबीएयू का नाम डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विचारक एवं समाज सुधारक से जुड़ा है, इसलिए यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षाएं भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है, जो मस्तिष्क, हृदय और हाथ, तीनों का विकास करे। मस्तिष्क से तार्किक एवं विवेकपूर्ण क्षमता, हृदय से मानवीय संवेदनाएं और हाथों के माध्यम से ज्ञान को व्यावहारिक कौशल में बदलने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ संवेदनशीलता आवश्यक है।रक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से राष्ट्र एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों का वास्तविक मूल्य तभी बढ़ता है, जब उनके साथ चरित्र और संस्कार जुड़े हों।

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है।

15 दिनों के भीतर दो बार एक मंच पर आएंगे मोदी-पुतिन और शी

देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब मध्य एशिया वैश्विक शक्ति संघर्ष का नया मैदान बन चुका है।

नीरज कुमार दुबे

भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने की पुष्टि करते हुए उनके उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दौरे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल-सी मच गयी है। हलचल इसलिए मची है क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीने पर पिछले साल की तरह फिर से सांप लोट सकते हैं। पिछली बार चीन के तियानजिन में एससीओ मंच पर इन तीन नेताओं की तस्वीर ने अमेरिकी रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा दी थी। तब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों को भारत-अमेरिका रिश्तों को दशकों पीछे धकेलने वाला कदम बताया था और कहा था कि ऐसी नीतियों ने मोदी को पुतिन और शी के और करीब पहुंचा दिया। अब दृश्य और बड़ा है। पहले मध्य एशिया, फिर नई दिल्ली यानि पहले एससीओ और उसके तुरंत बाद ब्रिक्स। संदेश साफ है कि भारत किसी की रणनीतिक जागीर नहीं है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब मध्य एशिया वैश्विक शक्ति संघर्ष का नया मैदान बन चुका है। चीन बेल्ट एंड रोड के जरिए अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, रूस इस क्षेत्र को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और अमेरिका भी यहां अपनी मौजूदगी तथा रणनीतिक पहुंच बनाए रखने की कोशिश में है। ऐसे में मोदी की सक्रिय कूटनीति भारत को खेल का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रही है।

उज्बेकिस्तान इस रणनीति का अहम केंद्र है। मोदी की प्रस्तावित ताशकंद यात्रा व्यापार, रक्षा, निवेश, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति दे सकती है। पिछले पांच वर्षों में भारत-उज्बेकिस्तान व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और द्विपक्षीय कारोबार लगभग 1.3 अरब डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख किया गया है। भारत का निवेश फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में फैला है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय भी उज्बेकिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।

लेकिन इस यात्रा की असली ताकत केवल व्यापार के आंकड़ों में नहीं है। उज्बेकिस्तान भारत की मध्य एशिया रणनीति का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पाकिस्तान द्वारा भूमि मार्ग अवरुद्ध रखने के कारण भारत के सामने संपर्क का प्रश्न लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा यानि आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक महत्व रखते हैं। ईरान और पश्चिम एशिया की मौजूदा अस्थिरता ने इन परियोजनाओं की राह कठिन जरूर बनाई है, लेकिन भारत के लिए विकल्प तलाशना अब मजबूरी नहीं, रणनीतिक आवश्यकता है।

अफगानिस्तान भी मोदी-मिर्जियोयेव वार्ता का बड़ा मुद्दा हो सकता है। स्थिर अफगानिस्तान के बिना दक्षिण और मध्य एशिया की कनेक्टिविटी, व्यापार और सुरक्षा की कोई भी बड़ी योजना अधूरी है। ताशकंद और नई दिल्ली पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर अधिक निकट समन्वय विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा सहयोग, 'दुस्तलिक' सैन्य अभ्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान-तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों में साझेदारी भारत की मध्य एशिया नीति को नई धार दे सकती है।

इसके बाद बिश्केक में एससीओ का मंच मोदी को रूस और चीन समेत प्रमुख यूरेशियाई शक्तियों के साथ सीधे संवाद का अवसर देगा। भारत के लिए एससीओ केवल फोटो-ऑप नहीं है। आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता, ये सभी भारत के प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हित से जुड़े प्रश्न हैं। नई दिल्ली लगातार यह भी रेखांकित करती रही है कि कनेक्टिविटी परियोजनाएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें तथा आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू मोदी-पुतिन संबंध हैं। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन ने मोदी से एससीओ में मिलने की इच्छा जताई और भारत के लिए उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की बात कही। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, परमाणु सहयोग और कृषि जरूरतों से जुड़े रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रूस के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं और यही मोदी की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन असली भू-राजनीतिक धमाका इसके बाद हो सकता है। 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन और शी चिनफिंग की मौजूदगी की संभावना भारत की कूटनीतिक हैसियत को और मजबूत करेगी। यदि मोदी, पुतिन और शी एक ही मंच पर लगातार दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मिलते हैं, तो यह किसी औपचारिक मित्रता की घोषणा नहीं होगी; लेकिन यह जरूर दिखाएगा कि विश्व राजनीति अब एकध्रुवीय निर्देशों पर नहीं चलती।

भारत, रूस और चीन के बीच मतभेद मौजूद हैं, विशेषकर भारत-चीन संबंधों में। इसलिए इसे किसी स्थायी त्रिपक्षीय गठबंधन के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। मगर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वैश्विक शासन सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज, ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक आर्थिक संस्थाओं के सवाल पर तीनों देशों की बातचीत का प्रभाव अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों तक जरूर पहुंचेगा। मोदी की उज्बेकिस्तान से बिश्केक और फिर नई दिल्ली तक फैली यह कूटनीतिक श्रृंखला एक बड़े संदेश का निर्माण करती है। संदेश यह है कि भारत अब मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंधों को नए आर्थिक आधार दे रहा है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और संवाद, दोनों को एक साथ साध रहा है और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए ग्लोबल साउथ की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन के लिए संदेश इसलिए असहज हो सकता है, क्योंकि दबाव, टैरिफ और रणनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारत को किसी खेमे में बांधने की गारंटी नहीं देती।

बहरहाल, मोदी की कूटनीति का मूल मंत्र साफ दिखाई देता है कि जहां भारत का हित, वहीं भारत का हाथ। अगले कुछ सप्ताह में ताशकंद, बिश्केक और नई दिल्ली के मंच शायद यही साबित कर दें कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अपनी शर्तों पर चाल चलने वाला निर्णायक खिलाड़ी है।

व्यंग्य

सीमा पर शांति का सर्वोच्च महत्त्व

उन कदमों पर विचार अनिवार्य है, जिनसे दुस्साहसी कार्रवाइयों को चीन के लिए महंगा बनाया जाए। ऐसा तभी हो सकता है, जब भारत के पास राष्ट्रीय सहमति से तैयार समग्र चीन नीति हो।

भारत- चीन संबंध में फिर पेच पड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर उचित कदम उठाया है कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति का सर्वोच्च महत्त्व है। बेशक, उस हाल में संबंध आगे बढ़ते नहीं रह सकते, जब सीमा पर अतिक्रमण या घुसपैठ की खबरें लगातार आ रही हों। हाल में कुछ ऐसे रील्स वायरल हुए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोग सीमा की रक्षा को लेकर भारत की कथित उदासीनता की चर्चा करते सुने गए। कुछ खबरों में दावा किया गया कि चीनी सेना के जवानों ने अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी ज़लि के ताकसिंग सर्कल में पुकार ला और ओल्लो के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा क्षेत्रों की स्थिति भारत-चीन संबंधों पर असर डालेगी। उसने दोहराया कि चीनी सैनिकों की घुसपैठ को भारत सबसे गंभीर मुद्दा मानता है, जिसे चीन से बातचीत में हमेशा उठाया गया है।

बहरहाल, सवाल है कि चीन भारत की इस चिंता का कितना ख्याल रख रहा है? भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से वह बाज क्यों नहीं आता? ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरकारी सूत्रों के सिर्फ ऐसे बयानों से नहीं मिल सकता कि भारतीय सेना और भारत- तिब्बत सीमा पुलिस सतर्क हैं और चीनी गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। इसलिए कि चीन अगर यह मान कर चलता है कि उसे नुकसान पहुंचाने लायक विकल्प भारत के पास नहीं हैं, तो वह अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहेगा। वहां के नीतिकारों की नजर निश्चित रूप से इस घटनाक्रम पर होगी कि सीमा पर की घटनाओं के बावजूद चीन से आयात बढ़ाने, और अब चीनी पूंजी को आमंत्रित करने की दिशा में भारत आगे बढ़ता गया है। साथ ही ऐसी खबरें भी नहीं आई हैं, जिनसे पता चले कि सीमा पर चीनी फौज को दो-टूक जवाब दिया गया हो। अतः उन कदमों पर विचार अनिवार्य है, जिनसे दुस्साहसी कार्रवाइयों को चीन के लिए महंगा बनाया जाए। ऐसा तभी हो सकता है, जब भारत के पास राष्ट्रीय सहमति से तैयार समग्र चीन नीति हो। अब इस दिशा में पहल की जरूरत है।

ब्लॉग

मराठी अस्मिताबोध की नई अभिव्यक्ति

उमेश चतुर्वेदी

महाराष्ट्र के ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कामचलाऊ मराठी भाषा जरूरी किए जाने को लेकर विवाद उठना स्वाभाविक है। यह विवाद बांबे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम को लागू करते हुए तर्क दिया है कि इससे यात्रियों और टैक्सी-ऑटो चालकों के बीच भरोसा बढ़ेगा और यात्रियों में सुरक्षा का भाव रहेगा। मोटे तौर पर सरकार की यह दलील बेहतर लगती है, लेकिन जब राज्य की टैक्सियों और ऑटो की संख्या और उनके चालकों पर ध्यान देते हैं तो यह सवाल सिर्फ भाषा का नहीं रह जाता, बल्कि उपराष्ट्रीयता के उभार और उसके बहाने राष्ट्रीयता के विचार को चुनौती का भी हो जाता है। इस सोच का सिरा आगे बढ़ते हुए हिंदी विरोध और प्रकारांतर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के प्रवासियों की मुखालफत तक जा पहुंचता है।

भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थन में 'विविधता में एकता' का पाठ हर भारतीय को स्कूली घुट्टी में मिला है। लेकिन जीवन की कठोर राहों पर उतरते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्रीयता की असल धारा जितनी गहरे तक हिंदी हृदय प्रदेशों में बहती है, उतनी गैर हिंदीभाषी प्रदेशों में नजर नहीं आती। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीयता के पुरजोर पोषक इन इलाकों को उपहास में कभी बीमारू कहा जाता था। इस पर गोबरपट्टी और गोबरनाडु का विशेषण खास धारा की वैचारिकी ने जो चस्पा कर रखा है। इस सोच की प्रमुख वजह आर्थिक रूप से इन इलाकों का अपेक्षाकृत उपराष्ट्रीयता वाले इलाकों से पिछड़े रहना है। इसी वजह से रोजी-रोटी की खातिर महाराष्ट्र के टैक्सी और ऑटो चालकों में सबसे बड़ी संख्या भदेस माने वाले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि के प्रवासी शामिल हैं। जाहिर है कि मराठी का कामचलाऊ ज्ञान रखने के नियम का शिकार यही लोग ज्यादा हुए हैं। इससे इनकी ही रोजी-रोटी पर संकट बढ़ा है।

महाराष्ट्र के ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य में 12 लाख 96 हजार से ज्यादा ऑटो हैं, जबकि करीब पांच लाख टैक्सियां हैं। यहां के परिवहन विभाग के मुताबिक, अकेले ग्रेटर मुंबई इलाके में करीब पांच लाख टैक्सियां और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। इनमें करीब 75 फीसद ऑटो-टैक्सी चालक गैर मराठी और हिंदीभाषी इलाकों के ही हैं। राज्य के दूसरे इलाकों में करीब आधे ऑटो-टैक्सी चालक हिंदीभाषी हैं। महाराष्ट्र ही क्यों, किसी भी राज्य के सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को वहां की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। उनके रोजाना का काम स्थानीय भाषा के कामचलाऊ ज्ञान से चल सकता है। बड़ा सवाल यह है कि मराठी के कामचलाऊ ज्ञान का पैमाना क्या हो, महाराष्ट्र सरकार का आदेश इस मसले में स्पष्ट नहीं है। विवाद और परेशानी इस वजह से भी है।

सर्विस सेक्टर और रेहड़ी-पटरी लगाने वाले अक्सर कामकाज करते-करते स्थानीय भाषा सीख लेते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हथकरघा और दस्तगारी का सामान बेचने वाली गुजराती महिलाएं कम शिक्षित हैं। लेकिन वे हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश भी धाराप्रवाह बोल लेती हैं। तमिलनाडु को लेकर धारणा है कि वहां घोर हिंदी विरोधी माहौल है। लेकिन वहां के प्रमुख पर्यटन स्थल महाबलीपुरम् में भीख मांगने वाले भी बहुभाषी मिल जाते हैं, जो हिंदीभाषी सैलानियों से हिंदी में भीख मांगते हैं। वहां घूम-घूमकर छोटे-मोटे सामान बेचने वाली लड़कियां भी तकरीबन अनपढ़ हैं, लेकिन वे हिंदी, गुजराती, बांग्ला आदि बोल लेती हैं। चाहे कनॉट प्लेस के फुटपाथ पर दस्तगारी का सामान बेचने वाली गुजराती महिलाएं हों या कोलकाता की गलियों में दुकान लगाने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हों, अगर वे अंग्रेजी और बांग्ला आदि बोलते हैं तो इसकी वजह कोई स्कूली शिक्षा नहीं, बल्कि रोजाना का संपर्क और जरूरत है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के ऑटो-टैक्सी चालक मराठी का कामचलाऊ ज्ञान या समझ नहीं रखते। यहां ध्यान रखने की बात है कि अपनी माटी से दूर जब कोई ऑटो या टैक्सी चलाने का काम चुनता है तो वह तत्काल सड़क पर नहीं उतरता। वह पहले सड़कों को पहचानता है, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है।

भाषा विज्ञान की नजर से देखें तो मराठी, गुजराती और राजस्थानी ऐसी भाषाएं नहीं है, जिन्हें आम हिंदीभाषी समझ नहीं सकता। ठीक इसी तरह इन भाषा-भाषियों के लिए हिंदी भी ऐसी भाषा नहीं है, जिसे वे न समझ सकें। भाषा को लेकर जब भी कोई विवाद उठता है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का एक इंटरव्यू याद आता है। जिसमें उन्होंने अपनी दादी की चारधाम यात्रा का जिक्र किया था। उनकी दादी ने शायद पिछली सदी के दूसरे दशक में तमिलनाडुके पालघाट इलाके के अपने गांव से चारधाम की यात्रा की थी और महीनों बाद सकुशल वापस लौट आई थीं। शेषन ने कहा था कि उनकी दादी तमिल के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं जानती थीं, लेकिन उन्हें चारधाम यात्रा से दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ शेषन ही नहीं, सदियों से लोग भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तीर्थ यात्राएं करते रहे हैं। आज तो तकनीक का विस्तार हो गया है, संचार क्रांति हो चुकी है। जब ये सहूलियतें नहीं थीं, तब क्या तीर्थ यात्राएं रूकीं। तब क्या भाषाएं बाधा बनीं। ऐसे में सवाल यह है कि फिर आज भाषा कैसे चुनौती बन सकती है।

कम ही लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए फजलुर्रहमान आयोग की रिपोर्ट ही भाषायी उपराष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाली रही। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसी के नजीतन भारतीय उपराष्ट्रीयताओं को अपनी भाषाओं के बहाने अपना वर्चस्व साबित करने का आधार मिल गया। इसी वजह से आए दिन राज्यों में अपनी भाषाओं को लेकर अस्मिताबोध जागता रहता है। इस बोध के निशाने पर अक्सर हिंदीभाषी ही रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मूल में भी मराठी उपराष्ट्रीयता और अस्मिताबोध रहा है। इस अस्मिताबोध को शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने पहली अभिव्यक्ति 1960 के दशक में मुंबई में मलयाली भाषा-भाषियों के खिलाफ आंदोलन के जरिए दी और बाद के दिनों में उनके भतीजे राज ठाकरे तो इस अस्मिताबोध के दबंग पैरोकार बनकर उभरे। केंद्र सरकार और बैंकों आदि की नौकरियों के लिए परीक्षा देने मुंबई-नासिक आदि पहुंचे हिंदीभाषी छात्रों को बाकायदा पीटकर इस भाषा बोध को राज ठाकरे के कथित सैनिक दिखाते रहे। वे भूल गए कि बंग-भंग के खिलाफ आंदोलन के दौरान 1905 में मराठी मानुष के पूज्य पुरूष बाल गंगाधर तिलक ने वाराणसी की यात्रा की थी। इस दौरान 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' में दिए एक व्याख्यान में उन्होंने पुरजोर तरीके से 'हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा ' घोषित किया था। मराठी अस्मिताबोध के शोर में तिलक की यह आवाज अक्सर खोती रही है।

एक खतरा यह भी है कि मराठी के कामचलाऊ ज्ञान की शर्त राज्य के दूसरे धंधे में काम कर रहे लोगों पर भी बाद में लागू हो सकती है। चूंकि उपराष्ट्रीयता वाले इलाकों में अपनी भाषा और संस्कृति का मसला लोगों के मर्म को छूता है, इसलिए राजनीति अक्सर इसे उभारने की कोशिश करती है। मौका देखकर आने वाले दिनों में राज्य में कार्यरत निर्माण मजदूरों आदि पर भी यह शर्त थोपी जा सकती है। इससे निश्चित तौर पर प्रवासी हिंदीभाषियों के लिए संकट पैदा होगा, उससे पलायन भी बढ़ सकता है। जिसकी कीमत राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योग को भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस मसले पर सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य रास्ता तलाशा जाए। नियमों को बेड़ी नहीं, लोक का सहयोगी होना चाहिए। इस नजरिए से भी इस बारे में विचार होना चाहिए।

आखिर में इस भाषा विवाद का एक सिरा देवेंद्र फड़णवीस के राजनीतिक करीयर से भी जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग उनमें राष्ट्रीय राजनीति की संभावना देखता है। महाराष्ट्र तक तो उनका मराठी अस्मिताबोध स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जब वे राष्ट्रीय राजनीति में सफल होने की कोशिश करेंगे, अपनी भाषा बोध के बहाने हिंदीभाषियों का विरोध उनकी राह की बाधा बन सकता है।

होटल में कत्ल!: सिर में कैसे लगी चोट? प्रेमी खामोश, बार-बार बदल रहा बयान, अंदरूनी अंग से हुआ अत्यधिक रक्तस्त्रव

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौट रही अनुसूचित जाति की 21 वर्षीय युवती की शिकोहाबाद स्थित एक होटल में प्रेमी के साथ ठहरने के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम में सिर में चोट लगने से कोमा में जाने के साथ अंदरूनी अंग से अत्यधिक रक्तस्राव की बात सामने आई है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी राहुल यादव और उसके एक साथी के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। परिजन ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया है जबकि उसका साथी फरार है। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चार घंटे तक प्रदर्शन किया। देर शाम युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नसीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती पिछले तीन माह से गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। रक्षाबंधन पर घर आने के लिए वह बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बस से गुरुग्राम से निकली थी। रात करीब आठ बजे शिकोहाबाद पहुंचने पर उसने पिता को फोन कर तबीयत खराब होने की बात कही। उसने बताया कि वह शिकोहाबाद की अपनी सहेली के घर रुक रही है और सुबह घर आ जाएगी। उसने पिता को अपने साथ राहुल उर्फ नितिन यादव निवासी विजेंद्र कॉलोनी के होने की भी जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार, युवती सहेली के घर पहुंची और अपना बैग वहां रख दिया। इसके बाद वह राहुल के साथ चली गई। दोनों मईयामई इलाके में एक होटल में ठहर गए। देर रात करीब तीन बजे युवती की हालत बिगड़ गई। राहुल ने सलेमपुर निवासी अपने एक दोस्त को बुलाया और दोनों युवती को बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। शिकोहाबाद मंडी के पास हाईवे किनारे स्थित अस्पताल में उस समय डायल-112 की टीम मौजूद थी। पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों के साथ अचेत युवती को देखा तो अस्पताल पहुंचे। तब तक चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों युवक वहां से निकलने लगे। पुलिस ने राहुल को हिरासत में ले लिया जबकि उसका साथी भाग निकला। पुलिस ने युवती के परिजन को घटना की सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता ने शव की पहचान करने के बाद राहुल और उसके साथी के खिलाफ तहरीर दी।

हम घटना के हर पहलू पर गहनता से जांच कर रहे हैं। पूरी विवेचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जा रही है। होटल के कमरे में क्या हुआ, कैसे युवती की जान गई फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है।

- अनुज चौधरी, एसपी देहात

युवती के सिर में कैसे लगी चोट?

मईयामई गांव के बाहर स्थित एक होटल के बंद कमरे में 21 वर्षीय युवती के साथ आखिर क्या हुआ यह रहस्य पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत का मुख्य कारण सिर में गंभीर चोट लगाया है। इसके अलावा अंदरूनी अंग से रक्तस्राव सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हिरासत में लिया गया मृतका का प्रेमी राहुल यादव पुलिस के सामने बार-बार अपने बयान बदलकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है।

आरोपी राहुल यादव से जब बंद कमरे में युवती के सिर पर लगी गहरी चोट के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो वह लगातार मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि युवती अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर गई थी, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। हालांकि, जब पुलिस ने चोट की गहराई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सामने रखा तो उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि युवती की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसका सिर दीवार में लग गया था।

शव रखकर गिरफ्तारी की मांग

बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने शिकोहाबाद-नसीरपुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजनों ने युवती की शिकोहाबाद निवासी सहेली की भूमिका की भी जांच कर उसे नामजद करने की मांग की। चार घंटे चले प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर स्थिति नियंत्रित हुई।

तीन डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ किया पोस्टमार्टम

युवती के शव का परीक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित तीन वरिष्ठ चिकित्सकों डॉ. राहुल जैन, डॉ. शालिनी तिवारी और डॉ. अभिषेक के पैनल ने किया। डॉक्टरों की टीम ने काफी गहनता से शरीर का परीक्षण किया। मौत के वास्तविक कारणों और दुष्कर्म के आरोपों की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए डॉक्टरों की टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जिनमें दुष्कर्म की आशंका और चिकित्सकीय पुष्टि के लिए डॉक्टरों ने तीन अलग-अलग स्लाइड सैंपल तैयार किए हैं।

अंदरूनी अंग से अत्यधिक रक्तस्त्रव की भी उलझी गुत्थी

युवती के अंदरूनी अंग से अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है लेकिन घटना के हालात कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब तलाशने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। आमतौर पर दुष्कर्म या हत्या के मामलों में पीड़िता द्वारा खुद को बचाने के लिए किए जाने वाले विरोध के निशान शरीर पर उभर आते हैं। हालांकि, फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों द्वारा की गई जांच में मृतका के शरीर पर खरोंच, दबाव या संघर्ष का एक भी निशान नहीं पाया गया है। यहां तक कि युवती के गले में पहनी हुई चेन भी बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत स्थिति में मिली है। उसके कपड़े भी फटे या अस्त-व्यस्त नहीं थे। शरीर और कपड़ों की सामान्य स्थिति के बावजूद युवती के अंदरूनी अंग से अत्यधिक रक्तस्राव होना सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। बिना किसी बाहरी जबरदस्ती या चोट के निशान के इतना गंभीर रक्तस्राव कैसे संभव हुआ इसको लेकर चिकित्सा विशेषज्ञ भी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसी कारण दुष्कर्म की शुरुआती थ्योरी पर भी संशय की स्थिति है।

साथ आती तो बच जाती बहन... बड़ी बहन ने रो-रोकर खोले कई राज

नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत मृतका की बड़ी बहन ने रो-रोकर कई राज खोले। बड़ी बहन ने बताया कि परिवार में पिता, मां और दो भाई व दो बहन हैं। पिता खेती करते हैं। दो में से एक भाई नोएडा में नौकरी करता है। मृतका दूसरे नंबर की थी। उसने आगरा के कुबेरपुर स्थित एक संस्थान से छह माह पहले तीन माह का नर्सिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था। उसी संस्थान के द्वारा बहन को गुरुग्राम के एक अस्पताल में साक्षात्कार के लिए भेजा गया। वहां साक्षात्कार ठीक नहीं होने के कारण नौकरी नहीं लगी। इस पर उसकी बहन ने एक कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए दोनों बहनों ने अपने गांव आने का प्लान बनाया था। बड़ी बहन ने बताया कि उसने छोटी बहन से एक साथ घर चलने को कहा था, लेकिन उसने साथ आने से इन्कार कर दिया। गुरुग्राम में मृतका के साथ उसी के गांव की एक अन्य युवती भी किराए के कमरे पर रहती है। वह उसके साथ आने की बात कह रही थी। मगर बहन उसके साथ बस में सवार नहीं हुई और दूसरी बस से आगरा तक आई। आगरा से उसने शिकोहाबाद के लिए बस पकड़ी थी। इस बीच उसकी सैलई, फिरोजाबाद निवासी फूफा से भी बात हुई थी। फूफा ने रात अधिक होने पर उनके घर आने के लिए कहा था। मगर बहन वहां भी नहीं पहुंची थी। बड़ी बहन के अनुसार, बुधवार रात करीब आठ बजे उसने शिकोहाबाद पहुंचने की जानकारी दी थी। बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वह एटा रोड पर स्थित अपनी एक सहेली के घर रुक रही है और अगले दिन सुबह गांव पहुंचेगी। वह साथ आती तो बज जाती।

दो साल से थे प्रेम संबंध

युवती और आरोपी राहुल यादव उर्फ नितिन निवासी विजेंद्र कॉलोनी के बीच पिछले करीब दो वर्षों से प्रेम संबंध थे। पुलिस को राहुल ने यह जानकारी दी है। उसने बताया कि युवती जब नौकरी करने गुरुग्राम गई थी, तब भी दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। रक्षाबंधन पर वह पांच दिन की छुट्टी लेकर आई थी। गुरुग्राम से आने से पहले ही दोनों का रात में होटल में रुकने का प्लान बना था। पुलिस अब दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और चैट की जांच कर रही है ताकि घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके।

दोस्त के जन्मदिन का बहाना बनाकर होटल गया था राहुल

राहुल यादव ने होटल में ठहरने और रात भर बाहर रहने के लिए अपने परिजन से झूठ बोला था। राहुल ने अपने परिवार को बताया था कि उसके दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए पार्टी में जाने के कारण उसे घर लौटने में देर हो जाएगी। इस झूठे बहाने की आड़ में वह गुरुग्राम से आई प्रेमिका से मिलने और होटल में रुकने पहुंचा था।

आरोपी का मजदूर परिवार बेहाल

आरोपी राहुल यादव का परिवार मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखता है। राहुल के पुलिस हिरासत में जाने की खबर मिलते ही उसके परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे थाने के चक्कर काटने लगे। वहीं मामले की संवेदनशीलता, सुरक्षा कारणों और निष्पक्ष पूछताछ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपी राहुल को थाने से हटाकर किसी सुरक्षित व गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया है, ताकि उस तक किसी की भी पहुंच न हो सके।

पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात रहा तीन थानों का फोर्स, पुलिस अभिरक्षा में गांव भेजा गया शव

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान थाना उत्तर, थाना नसीरपुर और थाना शिकोहाबाद की पुलिस टीम मुस्तैद रही। किसी भी अप्रिय घटना या हंगामे की आशंका को टालने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। पोस्टमार्टम की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नसीरपुर और शिकोहाबाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा घेरे में युवती के शव को उसके पैतृक गांव ले जाया गया।

पुलिस की रडार पर होटल संचालक

शिकोहाबाद। हाईवे स्थित मईयामई गांव के समीप दुकाननुमा कमरों में अवैध रूप से संचालित होटल का स्टाफ घटना के तुरंत बाद ताला बंद कर फरार हो गया। होटल के कमरे में युवती की हालत बिगड़ने या मौत होने पर संचालक ने पुलिस को कोई सूचना तक नहीं दी। स्थानीय लोगों के अनुसार एक व्यावसायिक इमारत में बने इन छोटे-छोटे दुकाननुमा कमरों को प्रेमी जोड़ों को घंटों के हिसाब से किराए पर दिया जाता था। बिना किसी वैध आईडी या इंद्राज के अवैध रूप से चल रहे इस होटल संचालक पर अब पुलिस का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में गिरी गाज, हेड कांस्टेबल सस्पेंड; आठ पर एफआईआर, गिरफ्तारी एक भी नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या में हिस्ट्रीशीटर राम लगन मौर्य की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूराकलंदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक सिंह को एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने सस्पेंड कर दिया है।

25 अगस्त को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कन्दैला गांव में गोली व बमबाजी कर हिस्ट्रीशीटर राम लगन मौर्य की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजमणि सिंह समेत आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है।

हत्याकांड के बाद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

मोहम्मद मुस्तफा ने सबको बराबरी से देखा

जौनपुर। नमाजे जुमा शिया जामा मस्जिद नवाब बाग में पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा व हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत 17 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से महफिल व मिलादे मासूमीन का इन्नेकाद किया गया महफिल की शुरुआत मोहम्मद समद खां ने तिलावते कुराने मजीद से किया महफिल को खिताब करते हुए मौलाना महफुजुल हसन खां ने कहा कि पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद ने एक ऐसे समाज की तश्कील की जिसमें सबको बराबरी की निगाह से देखा जाए मौलाना ने पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की सीरत पर रोशनी डाली और इमाम जाफर सादिक के फजायल ब्यान किए महफिल में हुसैन अब्बास जौनपुरी, अनवर जौनपुरी, हसरत जौनपुरी, वसीम जौनपुरी, मुश्ताक जौनपुरी, तालिब रजा शकील एडवोकेट, अफरोज जौनपुरी, मोहम्मद शफी, इश्तेयाक सलमानी ने कसीदा खानी की । सैय्यद असलम नकवी ने महफिल की निजामत किया।

सड़क हादसे में दो यवुकों की मौत

जौनपुर । जिले के बक्शा थाना क्षेत्र में प्रयागराज मार्ग पर फतेहगंज बाजार के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। कल रात हुई इस दुर्घटना में इलाज के दौरान शनिवार को दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।बताते है कि बीरभानपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अजीत कुमार यादव अपने घर से पशुओं के लिए चोकर लेने फतेहगंज बाजार गया था। चोकर लेकर वापस लौटते समय उसकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में अजीत कुमार यादव और दूसरी बाइक पर सवार 19 वर्षीय आफिर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आफिर सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के तमाशापुर गांव का निवासी था और उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ा।आफिर के साथ बैठा पुरानी बाजार कोतवाली निवासी रंजीत कुमार राव भी घायल हो गया, जिसे परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

रक्षाबंधन पर बहनों का दर्द : मुफ्त सफर की सौगात तो मिली, लेकिन बसें नहीं, बेवर बस स्टैंड का देखें हाल

आर्यावर्त संवाददाता

मैनपुरी। मैनपुरी के बेवर में रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा तो मिला, लेकिन बसों की कमी और यात्रियों की बेतहाशा भीड़ ने यह सुविधा मुसीबत में बदल दी। बेवर बस स्टैंड पर रक्षाबंधन से एक दिन पहले और त्योहार के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष बसों के इंतजार में घंटों खड़े रहे। दो से तीन घंटे इंतजार के बाद भी यात्रियों को बस में जगह नहीं मिल सकी। बस आते ही सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ जुटने लगी। जैसे ही कोई रोडवेज बस पहुंचती, उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ टूट पड़ती। सीट पाने की होड़ में महिलाएं और बुजुर्ग भी धक्का-मुक्की के बीच बस में प्रवेश करने को मजबूर हुए। बच्चों के साथ सफर कर रहे यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी।

त्योहार पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई, लेकिन उसके अनुरूप बसों की उपलब्धता नहीं दिखाई दी। बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई यात्री एक बस छूटने के बाद अगली बस के इंतजार में घंटों खड़े रहे। भीड़ अधिक होने के कारण कई यात्रियों को बस में चढ़ने का मौका तक नहीं मिला। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा से बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की जरूरत थी। लेकिन बेवर बस स्टैंड पर यात्रियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को हुई।

परिषदीय स्कूलों की बदहाली पर आप का प्रदर्शन, सुधार की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने शनिवार को बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिले के परिषदीय विद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जर्जर भवनों, जलभराव, खराब शौचालय, पेयजल की समस्या और बाउंड्रीवाल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया।

दुबे ने बताया कि आप की टीम ने प्रतापपुर कमैचा, जयसिंहपुर और मोतिगरपुर विकासखंड के कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के आधार पर तैयार ज्ञापन में स्कूलों की खराब स्थिति का विस्तृत उल्लेख किया गया है। रूपी का पूरा प्राथमिक विद्यालय जलभराव और कीचड़ से घिरा है। भवन जर्जर होने के साथ छतें टपक रही हैं और शौचालय अनुपयोगी हैं। रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय में तीन कमरों में कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई संचालित हो रही है। दरपीपुर के नए भवन की छत भी टपक रही है, जबकि लामा बनकटा विद्यालय भवन विहीन है। अन्य कई विद्यालयों में रास्ते, बाउंड्रीवाल, पंखे और जलनिकासी की समस्या बताई गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय मलवा में एक ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई संचालित होने का आरोप है। बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कहा गया था। आप ने जर्जर भवनों की मरम्मत, जलनिकासी, रास्तों और मूलभूत सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की मांग की है।

कुएं में डूबकर सगे भाइयों की मौत, मोटर निकालने उतरे थे दोनों, छोटे को बचाने में बड़े भाई ने भी गंवाई जान

आर्यावर्त संवाददाता

उरई। उरई जिले में कैलिया थाना क्षेत्र के करियावली गांव में शुक्रवार को कुएं में मोटर निकालने उतरे दो सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव के किनारे फूल सिंह कुशवाहा (65) और उनके छोटे भाई राम लखन कुशवाहा (55) का खेत है।

खेत में करीब 60 फीट गहरा कुआं है, जिससे पानी निकालने के लिए मोटर लगी थी। बारिश के कारण कुएं में पानी बढ़ने से मोटर पानी में डूबने लगी। इसे निकालने के लिए राम लखन रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, लेकिन वह पानी में डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए बड़े भाई फूल सिंह भी कुएं में उतर गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

रक्षाबंधन पर रोडवेज की व्यवस्थाएं ध्वस्त : बसों के लिए तरसीं बहनें, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली सीट

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां एक ओर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्सुक हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी रोडवेज की लचर व्यवस्था ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया है। फिरोजाबाद बस स्टैंड पर बसों की भारी किल्लत के चलते दूर-दराज जाने वाली महिला यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।

शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह से ही फिरोजाबाद बस स्टैंड पर बहनों और उनके परिवारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दावा तो किया गया, लेकिन स्टैंड पर पर्याप्त बसें न होने से यह दावा हवाई साबित हो रहा है। बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करने के बाद भी यात्रियों को बसें नसीब नहीं हो पा रही हैं।

प्रमुख रूटों पर बुरा हाल

फिरोजाबाद बस अड्डे से आगरा, मथुरा, इटावा, कानपुर, मैनपुरी, बरेली, औरैया और फर्रुखाबाद जैसे प्रमुख रूटों पर जाने वाली बसों का अकाल पड़ा हुआ है। जो बसें आ भी रही हैं, वे पहले से ही ठसाठस भरी हुई हैं। आलम यह है कि चलती बसों में चढ़ने के लिए महिलाओं और बच्चों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

यात्रियों में बढ़ा आक्रोश

घंटों से भीषण गर्मी और धूप में बस का इंतजार कर रही महिलाओं का गुस्सा रोडवेज प्रशासन के खिलाफ फूट रहा है। यात्रियों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार पर परिवहन निगम को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बसों के न मिलने से कई बहनें समय पर अपने भाइयों के घर पहुंचने को लेकर चिंतित हैं। वहीं, मजबूरी में कई यात्री डग्गामार और निजी वाहनों में भारी किराया देकर सफर करने को मजबूर हैं।

अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर,एक की मौत

कुड़वार/सुल्तानपुर। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर अनियंत्रित कार ने दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है।

शुक्रवार को बंधुआ कला थाना क्षेत्र में दादूपुर गांव में हाइवे कट के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने अरविंद(30) पुत्र राम सुमेर निवासी रामपुर चांदा व कक्कू(17) पुत्र त्रिभुवन निवासी इशुपुर चांदा ने टक्कर मार दी। जो सुल्तानपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। गंभीर हालत में इलाज के लिए दोनों घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।जहां ईलाज के दौरान अरविंद की मौत हो गई। जबकि कक्कू का इलाज अस्पताल में चल रहा है। थानाध्यक्ष बंधुआ कला प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा नगर कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया है।

09 वर्ष बाद अपने बेटे को देख मां बाप की आँखे हुई नम

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुल्तानपुर। 09 वर्ष पूर्व गांव के रिश्तेदार के साथ खलासी का काम करने गए किशोर के अचानक घर पहुंचने पर परिवार की आंखे नम हो गई। जो माता पिता बेटे की उम्मीद छोड़ चुके थे उनके बेटे के सामने आने पर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और दोनों की आंखें नम हो गई।

बता दे कि 20 अगस्त 2017 को स्थानीय थाना क्षेत्र के कालू का पुरवा भंडरा परशुराम गांव निवासी त्रिभुवन नाथ पाठक ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनका 14 वर्षीय बेटा सौरभ को गांव के रिश्तेदार ट्रक चालक संजय चौबे निवासी चौबे का पुरवा शालीपुर बीकापुर अयोध्या ट्रक पर खलासी का कार्य करने के लिए ले गया था।जब सौरभ के पिता ने रिश्तेदार से बात कराने को कहा तो उसने बताया कि वह कही चला गया उनके पास नहीं है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर काफी खोजबीन की लेकिन किशोर का पता नहीं चल सका।थकहारकर पुलिस ने भी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जिसके बाद माता पिता ने बेटे की उम्मीद छोड़ दी। दो वर्ष पूर्व लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में एक मंदबुद्धी युवक को सौरभ के पिता अपना बेटा समझ कर घर लेकर आ गए थे।लेकिन 02 दिन पूर्व जब उनका असली बेटा घर पहुंचा तो पिता त्रिभवन नाथ सहित अन्य परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंचे सौरभ ने बताया कि जब खलासी का काम करने गया था तो वह दिल्ली के पास ट्रक से दूध लेने उतरा था जब वापस लौटा तो ट्रक नहीं मिली। उसके बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शामली पहुंचा दिया। जहां उसे एक बड़े तबेले में बंधक बना लिया गया। दो माह पूर्व वह किसी तरह वहां से निकल पाया तो उसने पुलिस की शरण ली।लेकिन पुलिस से मदद न मिलने के बाद उसे एक मुस्लिम युवक अपने साथ गाजियाबाद लेकर चला गया और एक माह काम करने के बाद जब सौरभ ने घर आने की इच्छा जताई तो उसने 10 हजार रुपया देकर सुल्तानपुर की ट्रेन पर बैठा दिया। सौरभ के घर पहुंचते ही परिवार में खुशी का माहौल हो गया।

देश में बारिश हो रही है, फिर भी अनाज के उत्पादन पर संकट क्यों?

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। इसका सीधा असर खाद्यान्न संकट के साथ-साथ खाद्य कीमतों पर पड़ने की आशंका है।

असमान मानसून से खेती पर बढ़ी चिंता

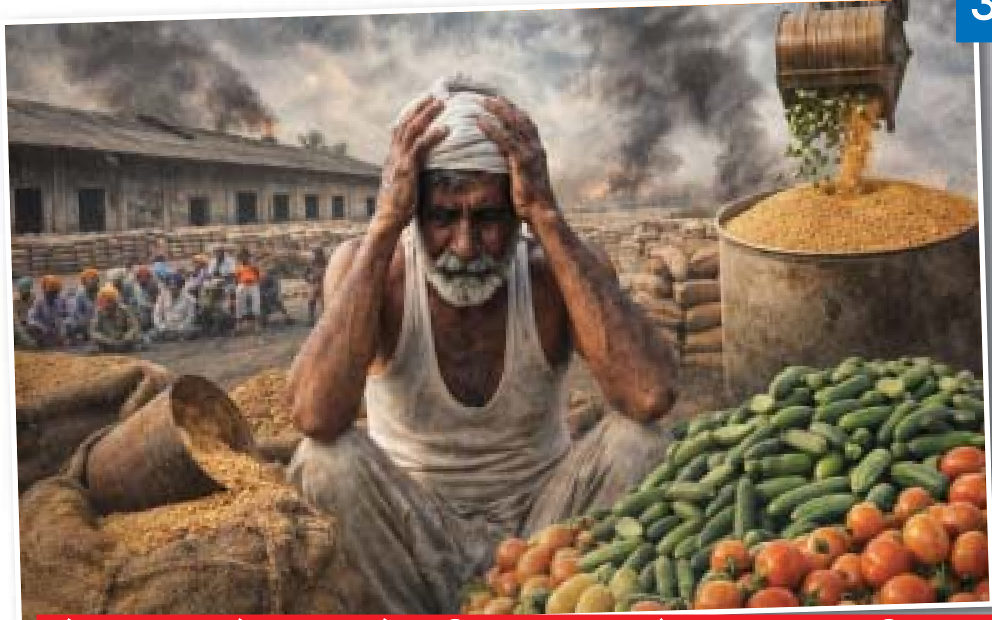

गेहूं, चावल के साथ सोयाबीन, मक्का और अरहर पर भी संकट

देश के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश हो रही है। मौसम विभाग भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आसमान से पानी बरस रहा है तो फिर अनाज के उत्पादन पर संकट की बात क्यों हो रही है?

दरअसल, राष्ट्रीय स्तर पर बारिश का आंकड़ा पूरी तस्वीर नहीं बताता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के ताजा आकलन के मुताबिक 2026 का मानसून क्षेत्रीय स्तर पर बेहद असमान रहा है।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के बारिश के तनाव यानी कम बारिश की स्थिति से गुजर रहे हैं। NCAER ने कहा है कि ऐसे इलाकों में खरीफ उत्पादन पर राष्ट्रीय बारिश के आंकड़े से कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

पांच राज्यों में कम बारिश क्यों चिंता की बात है?

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात बड़े कृषि प्रधान राज्य हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 35.77 करोड़ टन रहा

इसमें मध्य प्रदेश का योगदान करीब 4.66 करोड़ टन, राजस्थान का 2.56 करोड़ टन रहा।

महाराष्ट्र के 1.85 करोड़ टन, कर्नाटक के 1.46 करोड़ टन और गुजरात के करीब 1.05 करोड़ टन रहे।

इन पांच राज्यों को जोड़ दें तो उत्पादन करीब 11.58 करोड़ टन बैठता है।

देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 32 प्रतिशत अकेले इन्हीं पांच राज्यों से आता है।

इसलिए इन राज्यों में बारिश का संकट केवल स्थानीय किसानों की समस्या नहीं है।

यहां बारिश की कमी का असर देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा। उसमें कमी आएगी।

इसका असर पहले खाद्य कीमतों पर पड़ेगा। किसानों की आय में भी गिरावट आ सकती है।

सिर्फ बारिश होना काफी क्यों नहीं?

खेती के लिए बारिश की मात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि बारिश कब, कहां और कितनी देर होती है। अगर इलाके में पूरे महीने की बारिश एक-दो दिन में बहुत ज्यादा हो जाए और उसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ जाए। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में कुल बारिश सामान्य दिख सकती है। लेकिन खेती के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल, किसान के खेत में फसल को उस समय पानी नहीं मिला जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में फसल के उत्पादन में गिरावट जरूर आएगी।

खरीफ फसलों के उत्पादन पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों?

खरीफ फसलों के लिए यह स्थिति और गंभीर है। बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी चाहिए। फसल के शुरुआती विकास, फूल आने और दाना बनने के समय भी पानी की जरूरत होती है। अगर जरूरत के समय बारिश नहीं होती है तो बाद में होने वाली तेज बारिश भी पहले हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगी। इस साल सवाल केवल यह नहीं है कि देश में कितनी बारिश हुई, बल्कि यह है कि बारिश खेती वाले इलाकों में कितनी पहुंची।

गेहूं, चावल के अलावा अन्य किन अनाजों उत्पादन प्रभावित होगा?

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में खेती का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है। यहां सिंचाई की सुविधा सीमित है। जरूरत के समय बारिश ना होने की स्थिति इन राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।अरहर, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।बारिश की कमी का असर केवल गेहूं या चावल जैसे प्रमुख अनाज तक सीमित नहीं रहेगा। दाल और मोटे अनाज का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अबकी बार मॉनसून की सबसे बड़ी चुनौती इसका असमान होना रहा है। एक तरफ कुछ राज्यों और जिलों में लगातार भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्रों में बारिश की कमी बनी हुई है। इसका मतलब है किहर कृषि क्षेत्र को फसल की जरूरत के मुताबिक पानी मिल रहा है।

अनाज उत्पादन पर क्या पड़ेगा असर?

अगर बारिश की कमी वाले राज्यों में आने वाले दिनों में पर्याप्त और समय पर बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इसका असर किसानों की आय पर पड़ेगा। उत्पादन घटने पर बाजार में दाल, अनाज, तिलहन और कुछ दूसरी कृषि उपज की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है।कमजोर मानसून का असर केवल इस मौसम की फसल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले रबी सीजन की तैयारी पर भी पड़ सकता है।

रोज माउथवॉश करते हैं तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, वर्ना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

सुबह उठते ही ब्रश करना और फिर मुंह की ताजगी के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करना अब कई लोगों की रोज की आदत बन चुका है। कुछ लोग इसे सांसों की बदबू दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ को लगता है कि माउथवॉश करने से दांत और मसूड़े ज्यादा साफ रहेंगे। हालांकि माउथवॉश मुंह की सफाई में मदद जरूर करता है, मगर यह ब्रश और दांतों के बीच की सफाई नहीं कर सकता। साथ ही, हर दिन इस्तेमाल करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आप किस तरह का माउथवॉश इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है। माउथवॉश से कुल्ला करने के बाद मुंह ताजगी भरा जरूर लगता है, लेकिन इससे दांतों पर जमी गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती। ब्रश दांतों की सतह पर जमा गंदगी और प्लाक को हटाने में मदद करता है। वहीं दांतों के बीच फंसे खाने को साफ करने के लिए के लिए फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश की जरूरत पड़ती है। इसलिए माउथवॉश को ब्रश का विकल्प मानना गलत है। इसे जरूरत के मुताबिक रोज की ओरल हाइजीन रूटीन में शामिल किया जा सकता है।

बाजार में कई तरह के माउथवॉश मिलते हैं। किसी का इस्तेमाल बदबू के लिए किया जाता है, तो किसी को मसूड़ों या दूसरी दांतों की परेशानी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए सिर्फ अच्छा स्वाद या बड़ी कंपनी देखकर माउथवॉश खरीदना सही नहीं है। अगर आपको दांत या मसूड़ों से जुड़ी कोई परेशानी है तो डेंटिस्ट से पूछकर माउथवॉश लेना बेहतर रहेगा।

कुछ माउथवॉश इस्तेमाल करने पर मुंह में तेज जलन होती है। कई लोगों को लगता है कि जलन ज्यादा है तो माउथवॉश ज्यादा असरदार होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जलन कुछ खास चीजों की वजह से हो सकती है, जैसे अल्कोहल या उसमें डाला गया फ्लेवर। अगर हर बार इस्तेमाल के बाद ज्यादा जलन या परेशानी हो रही है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

माउथवॉश खरीदने से पहले उसकी बोतल पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें। उसमें कौन-कौन सी चीजें डाली गई हैं, यह देखना जरूरी है। खासकर अगर आपका मुंह जल्दी सूखता है या किसी चीज से जलन होती है तो ऐसा प्रोडक्ट चुनने से बचें, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हर व्यक्ति के लिए एक ही माउथवॉश सही हो, यह जरूरी नहीं है।

अगर माउथवॉश करने के बाद सांसों की बदबू वापस बनी रहती है तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। दांतों और मसूड़ों की बीमारी भी इसकी वजह बन सकती है। ऐसे में बार-बार माउथवॉश करने के बजाय डेंटिस्ट से जांच कराना ज्यादा बेहतर रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में हर 2 में से एक लोग सिरदर्द से परेशान, माइग्रेन-टेंशन के सबसे ज्यादा केस

भारत में सिरदर्द आम परेशानी से कहीं बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। दिल्ली-NCR में 67 .9% लोगों ने पिछले साल सिरदर्द की शिकायत बताई, जबकि 26% को विशेषज्ञ इलाज से फायदा हो सकता है।

>> भारत में 67.9% लोगों ने सिरदर्द की परेशानी बताई >> 26% लोगों को विशेषज्ञ इलाज से फायदा मिल सकता है

>> तनाव वाला सिरदर्द, माइग्रेन से भी ज्यादा आम पाया गया >> क्या बार-बार दर्द की दवा लेना सिरदर्द को बढ़ा सकता है?

सिरदर्द को हम आमतौर पर ऐसी परेशानी मानते हैं जो थोड़ी देर आराम करने या कोई दवा लेने के बाद ठीक हो जाएगी। काम का तनाव हो, नींद पूरी न हुई हो, लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर जोर पड़ा हो या दिनभर की भागदौड़ हो हम अक्सर सिरदर्द की वजह ढूंढकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, भारत में हुई नई रिसर्च की तस्वीर बताती है कि सिरदर्द सिर्फ कभी-कभार होने वाली मामूली परेशानी नहीं है।

दिल्ली और एनसीआर में किए गए एक बड़े आबादी आधारित अध्ययन में 18 से 65 साल की उम्र के लोगों में पिछले एक साल के दौरान किसी न किसी तरह का सिरदर्द 67.9 फीसदी लोगों में पाया गया। यानी हर 100 लोगों में करीब 68 लोगों ने सिरदर्द की समस्या बताई। वहीं उत्तर भारत के ग्रामीण इलाके में हाल में हुई एक दूसरी स्टडी में यह आंकड़ा 53.6 फीसदी रहा। दोनों अध्ययनों की आबादी और जगह अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं, सिरदर्द बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है।

हर पांच में एक को इलाज की जरूरत

AIIMS की स्टडी में सिरदर्द से परेशान लोगों ने औसतन अपने 9.5 फीसदी समय को मध्यम तीव्रता वाले सिरदर्द के साथ बिताया। पूरे वयस्क आबादी के स्तर पर अनुमान लगाया गया कि लोगों का करीब 5.5 से 6.6 फीसदी समय किसी न किसी तरह के सिरदर्द में गुजर सकता है। इसी अध्ययन के मुताबिक, 18 से 65 साल की आबादी में करीब 26 फीसदी लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल से फायदा हो सकता है।

सिरदर्द से घट रही काम करने की क्षमता

दूसरी ओर ग्रामीण उत्तर भारत की स्टडी में भी करीब एक-पांचवां हिस्सा ऐसे लोगों का मिला जिन्हें विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा से फायदा पहुंच सकता है। जिसका मतलब ये है कि सिरदर्द सिर्फ दर्द की शिकायत नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की काम करने की क्षमता से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी बन सकता है।

67.9%: दिल्ली-एनसीआर में 18-65 साल की आबादी में किसी भी तरह के सिरदर्द की एक साल की दर।

53.6%: ग्रामीण उत्तर भारत की दूसरी स्टडी में किसी भी सिरदर्द की एक साल की दर।

26.3%: दिल्ली-एनसीआर अध्ययन में माइग्रेन से परेशान लोगों की अनुमानित दर।

34.1%: दिल्ली-एनसीआर में तनाव से होने वाले सिरदर्द की अनुमानित दर।

26% : दिल्ली-एनसीआर की 18-65 साल की आबादी में ऐसे लोगों का अनुमान, जिन्हें विशेषज्ञ सिरदर्द इलाज से फायदा हो सकता है।

3.7% : ग्रामीण उत्तर भारत की स्टडी में सिरदर्द वाले लोगों का पिछले महीने सिरदर्द के लक्षणों में बिताया गया औसत समय।

माइग्रेन ही सबसे बड़ी परेशानी नहीं

सिरदर्द का नाम आते ही सबसे पहले माइग्रेन का ख्याल आता है, लेकिन हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता। तनाव से होने वाला सिरदर्द भी बहुत आम है। दिल्ली-एनसीआर के अध्ययन में तनाव से होने वाले सिरदर्द की अनुमानित दर 34.1 फीसदी और माइग्रेन की 26.3 फीसदी थी। ग्रामीण उत्तर भारत के अध्ययन में भी तनाव से होने वाला सिरदर्द 28.9 फीसदी के साथ सबसे आम प्रकार रहा, जबकि माइग्रेन 18.7 फीसदी लोगों में पाया गया।

माइग्रेन कम लोगों में हो, फिर भी बोझ ज्यादा

दिल्ली-एनसीआर की रिसर्च में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। माइग्रेन की दर तनाव से होने वाले सिरदर्द से कम थी, लेकिन जिन लोगों को माइग्रेन था, उनके लिए इसका व्यक्तिगत बोझ काफी ज्यादा था। अध्ययन में माइग्रेन की वजह से स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान भी महत्वपूर्ण पाया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, माइग्रेन अकेले ही करीब 16.1 फीसदी आबादी को ऐसी श्रेणी में रखता है जिसे विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल से फायदा मिल सकता है।

सबसे ज्यादा परेशानी कब बढ़ती है?

रिसर्च में उन लोगों पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें महीने में 15 या उससे ज्यादा दिन सिरदर्द होता है। ऐसे लोगों में समस्या कहीं ज्यादा गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर के अध्ययन में इस तरह के सिरदर्द को एक अलग श्रेणी में रखा गया। इस समूह और दवा के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले सिरदर्द वाले लोगों में सिरदर्द का बोझ माइग्रेन या सामान्य तनाव वाले सिरदर्द से ज्यादा पाया गया।

समस्या की वजह जरूरी

यहीं एक और अहम बात सामने आती है- सिरदर्द की दवा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी समस्या बढ़ा सकता है। दिल्ली-एनसीआर अध्ययन में दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले संभावित सिरदर्द की दर 3 फीसदी थी। ग्रामीण उत्तर भारत की रिसर्च में यह आंकड़ा 2.8 फीसदी रहा। दवा का इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद अगर सिरदर्द बार-बार लौट रहा है, तो सिर्फ बार-बार दर्द की दवा लेने के बजाय समस्या की सही वजह समझना जरूरी हो सकता है।

सिरदर्द सिर्फ दर्द नहीं, समय का भी नुकसान

सिरदर्द का असर सिर्फ उस समय महसूस नहीं होता जब व्यक्ति दर्द में होता है। इसका असर घर के काम, नौकरी और दूसरी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर की स्टडी के मुताबिक पूरे आबादी स्तर पर करीब 5.5 फीसदी समय सिरदर्द के साथ गुजरने का अनुमान लगाया गया।

सिरदर्द की वजह से हर व्यक्ति के वेतन वाले काम में औसतन 0.1 दिन और घरेलू काम में 0.6 दिन प्रति महीने का नुकसान अनुमानित किया गया। ग्रामीण उत्तर भारत की रिसर्च में भी शोधकर्ताओं ने सिरदर्द को स्वास्थ्य नुकसान और काम करने की क्षमता में कमी से जोड़ा। यानी लगातार सिरदर्द व्यक्ति की जिंदगी में छोटे-छोटे नुकसान जोड़ता जाता है, जो लंबे समय में बड़ा असर पैदा कर सकते हैं।

टाटा-मिस्त्री में सुलह की सुगबुगाहट: चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद बढ़ी बातचीत; किन विकल्पों पर हो रहा विचार?

टाटा संस और साइरस मिस्त्री परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद में अब समझौते की राह बनती दिख रही है। भारी कर्ज के दबाव में एसपी ग्रुप टाटा संस में अपनी 18.4% हिस्सेदारी से नकदी जुटाने के विकल्प तलाश रहा है। क्या नोएल टाटा की अगुवाई में दोनों परिवारों के बीच वर्षों पुराना टकराव अब खत्म हो पाएगा

टाटा संस और साइरस मिस्त्री परिवार के बीच वर्षों से चला आ रहा ऐतिहासिक कॉरपोरेट टकराव अब एक निर्णायक और व्यावहारिक समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। शापूरजी पलोनजी समूह (एसपी ग्रुप) पर लदे भारी-भरकम और महंगे कर्ज के बोझ ने दोनों पक्षों को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है, जहां टाटा संस में मिस्त्री परिवार की 18.4 फीसदी हिस्सेदारी को भुनाने के फॉर्मूलों पर गोपनीय बातचीत चल रही है।

सूत्रों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के प्रतिनिधि एसपी ग्रुप के साथ नकदी जुटाने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख विकल्प यह है कि टाटा संस की 18.4 फीसदी हिस्सेदारी के बदले एसपी ग्रुप को टाटा समूह की लिस्टेड कंपनियों जैसे टाटा पावर आदि के शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएं।

चेयरमैन के इस्तीफे के बाद क्या हुआ

टाटा संस में 66 फीसदी की बहुलांश हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स की कमान नोएल टाटा के हाथों में आने और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के फरवरी में पद छोड़ने की घोषणा के बाद से इन वार्ताओं ने गति पकड़ी है। असल में बातचीत की सबसे अहम कड़ी पारिवारिक रिश्तेदारी है।

नोएल टाटा का विवाह एसपी ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन शापूर मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री से हुआ है। ऐसे में कड़वे कानूनी मुकदमों के बजाय एक सौहार्दपूर्ण वित्तीय समझौते की संभावना पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जा रही है। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा संस का रवैया इस डील के प्रति सख्त रहा था।

एसपी ग्रुप की मजबूरी

एसपी ग्रुप के लिए यह समझौता असल में मजबूरी बन चुका है। समूह ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े प्राइवेट क्रेडिट सौदों में से एक के तहत भारी फंड जुटाया है। समूह की इकाई इक्विजेन इनवेस्टमेंट ने 18.95 फीसदी के भारी ब्याज पर 36 महीने के बॉन्ड जारी किए हैं।

बॉन्ड का पहला बड़ा भुगतान जुलाई 2028 तक होना है...ऐसे में अगले 18 महीनों के भीतर एसपी ग्रुप को अपने महंगे कर्ज को निपटाने के लिए इस हिस्सेदारी से नकदी निकालनी ही होगी।

मूल्यांकन सबसे बड़ी चुनौती

इस संभावित सौदे में सबसे बड़ा रोड़ा टाटा संस का सटीक वैल्यूएशन तय करना है। टाटा संस देश के नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैले 100 से अधिक ऑपरेटिंग कंपनियों के विशाल साम्राज्य की नियंत्रक कंपनी है।

लिस्टेड कंपनियों का बाजार भाव तय है, लेकिन टाटा संस के पास एअर इंडिया और आईफोन बनाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विशाल अनलिस्टेड कंपनियां भी हैं, जिनकी सही वैल्यू तय करना दोनों पक्षों के लिए आसान नहीं होगा।

शेयरों की अदला-बदली में लिस्टेड कंपनियों के शेयर शामिल होने के कारण सेबी के टेकओवर कोड, खुले बाजार नियमों और आरबीआई के एनबीएफसी लिस्टिंग दिशा-निर्देशों के कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा होगी।

त्योहार से पहले महंगाई की मार : मुंबई में एक सितंबर से नौ रुपये लीटर महंगा होगा दूध, क्यों बढ़ाई गई कीमत?

मुंबई में रोजाना ताजा तबेला दूध खरीदने वाले लोगों को एक सितंबर से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दूध उत्पादकों ने कीमत में नौ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके बाद 93 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला तबेला दूध 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। नई दरें एक सितंबर, 2026 से लागू होंगी और 28 फरवरी, 2027 तक प्रभावी रहेंगी। यह बढ़ोतरी त्योहारों के मौसम से ठीक पहले हुई है, जिससे मुंबई के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

पशु, चारा और फीड महंगे होने से बढ़ी कीमत

मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अनुसार, डेयरी पशुओं की कीमत बढ़ने और पशु आहार पर खर्च बढ़ने के कारण दूध की पुरानी कीमत पर बिक्री करना मुश्किल हो रहा था।उत्पादकों का कहना है कि अनाज समेत कई तरह के पशु आहार की कीमतों में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। चारे और ऑयल केक की बढ़ी कीमत ने भी दूध उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। उनके मुताबिक, लगातार बढ़ती लागत के कारण कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था।

रोज दूध खरीदने वाले परिवारों पर सीधा असर

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ सकता है, जो रोजाना तबेला दूध खरीदते हैं। अब उन्हें हर लीटर पर 9 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी 1 सितंबर से मुंबई में तबेला दूध खरीदने पर 93 रुपये की जगह 102 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। त्योहारों के मौसम से पहले यह बढ़ोतरी घरेलू खर्च में एक और अतिरिक्त बोझ जोड़ सकती है। उत्पादकों ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती उत्पादन लागत को मुख्य वजह बताया है। नई दरें 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगी।

BRICS में भारत का बड़ा प्लान, 11 देशों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने की तैयारी

भारत अगले महीने होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच आसान और तेज डिजिटल पेमेंट का प्रस्ताव रख सकता है। इसके साथ ही भारत BRICS देशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर देगा। BRICS का शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। इस दौरान इस संगठन के 20 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा।

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सीमा पार डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए एक बेहतर सिस्टम तैयार करने पर चर्चा चाहता है। इसके अलावा BRICS देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े सिस्टम को समझने और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अगले सप्ताह एक हाईलेवल बैठक हो सकती है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि BRICS देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, भारत की यह पहल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य BRICS देशों के बीच व्यापार और डिजिटल लेनदेन को आसान बनाना है। भारत ऐसे सिस्टम पर भी काम करना चाहता है, जिससे अलग-अलग देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ सकें। इससे सीमा पार भुगतान जल्दी हो सकता है और लेनदेन की लागत भी कम हो सकती है।

भारत का केंद्रीय बैंक RBI पहले से CBDC का पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। अब RBI BRICS देशों के बीच सीमा पार डिजिटल लेनदेन में CBDC के इस्तेमाल की संभावनाएं भी देख रहा है। हालांकि, अभी ज्यादातर देशों में CBDC पूरी तरह लॉन्च नहीं हुई है। अलग-अलग देश इसके इस्तेमाल, तकनीक और सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती इंटरऑपरेबिलिटी यानी अलग-अलग देशों की डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ना है। इसके लिए देशों को तकनीक और नियमों में तालमेल बनाना होगा। चीन समेत कुछ BRICS देश पहले से डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं।

ब्राजील चुनाव: टीवी-रेडियो पर शुरू होगा घमासान, लूला और फ्लावियो बोल्सोनारो आमने-सामने

ब्राजील। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अब और तेज होने वाला है। शुक्रवार से राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो टीवी और रेडियो पर मुफ्त विज्ञापनों के जरिए लोगों से वोट मांगेंगे। सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद ब्राजील में टीवी और रेडियो आज भी चुनाव प्रचार का बड़ा माध्यम हैं। इन विज्ञापनों से देश के दूर-दराज के इलाकों तक भी उम्मीदवारों की बात पहुंचती है और चुनावी मुद्दे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति लूला चौथी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सबसे बड़े बेटे हैं। दोनों इस समय सर्वे में लगभग बराबरी पर बताए जा रहे हैं।

इस बार का चुनाव क्यों है खास?

राजनीतिक सलाहकार और ब्राजील के पूर्व मंत्री थॉमस ट्राउमन का मानना है कि इस बार चुनाव प्रचार काफी आक्रामक हो सकता है। उनका कहना है कि 2022 का राष्ट्रपति चुनाव पहले ही ब्राजील के इतिहास के सबसे कटु चुनावों में से एक था और इस बार प्रचार उससे भी ज्यादा तीखा हो सकता है। 2022 में लूला ने जायर बोल्सोनारो को बहुत कम अंतर से हराया था। जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश के मामले में 27 साल की जेल की सजा मिली है।

ब्राजील में राजनीतिक दलों को टीवी और रेडियो पर विज्ञापन के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। विज्ञापन का समय पार्टियों को उनके गठबंधन के आकार और निचले सदन में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर मिलता है। साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूनो पोम्पेउ के मुताबिक, इससे अमीर और गरीब पार्टियों के बीच प्रचार के साधनों में अंतर कम होता है।

प्रचार के लिए क्या हैं नियम?

4 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। उससे पहले टीवी और रेडियो चैनलों को हर दिन करीब 14 मिनट का समय लगभग 1,000 अलग-अलग 30 सेकंड के विज्ञापनों के लिए देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए रोज 12 मिनट 30 सेकंड का अलग समय रखा जाएगा। इसमें लूला और उनके सहयोगी दलों को 5 मिनट 31 सेकंड, जबकि फ्लावियो बोल्सोनारो की पार्टी को 4 मिनट 20 सेकंड मिलेंगे। बचा हुआ समय दो अन्य पार्टियों में बांटा जाएगा। फ्लावियो को कम समय मिलने से पता चलता है कि वह बड़े दलों को अपने साथ जोड़ने में लूला से पीछे हैं। 2018 में उनके पिता जायर बोल्सोनारो बड़े दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे थे। अगर चुनाव दूसरे चरण में जाता है तो 25 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में दोनों उम्मीदवारों को बराबर प्रचार समय मिलेगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया का असर टीवी और रेडियो के विज्ञापनों पर भी दिखाई देगा। विज्ञापन पहले की तुलना में ज्यादा सहज और कम बनावटी हो सकते हैं। प्रचार के लिए पहले टीवी और रेडियो पर खर्च होने वाला कुछ पैसा अब सोशल मीडिया सामग्री बनाने में भी लगाया जा सकता है।

तिब्बत में ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्री अब भी लापता, 19 देशों के हैं लोग

काठमांडू, एजेंसी। ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप दो दिन पहले चीन-नेपाल सीमा के पास के इलाकों में अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हो गया था। ग्रुप के कोऑर्डिनेटर ने शुक्रवार को बताया कि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। भारतीय आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) द्वारा स्थापित संगठन, ईशा फ़ाउंडेशन के नेतृत्व वाला यह 77 सदस्यों का ग्रुप संपर्क से बाहर है। ग्रुप की कोऑर्डिनेटर मां गंभीरी ने बताया कि सद्गुरु मदद के लिए आपदा प्रभावित मुख्य इलाके (ग्राउंड ज़ीरो) ग्यिरोंग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जरूरी मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि समूह में 19 देशों के लोग शामिल थे और उन्होंने हर तरह की मदद पाने के लिए भारत, चीन और नेपाल में सभी दूतावासों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जानकारी और मदद पाने के लिए उन्होंने भारत और नेपाल के कई दफ्तरों और मंत्रालयों से भी संपर्क किया। मां गंभीरी ने कहा, पिछले दो दिनों से ईशा फाउंडेशन के लापता 77 तीर्थयात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव दल मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 77 परिवार बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यह उनके लिए बहुत मुश्किल और भावुक समय है। ईशा फाउंडेशन हर सीजन में कई बार कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। ग्रुप काठमांडू से नेपाल होते हुए तिब्बत जाते हैं और यात्रा के दौरान पैदल ट्रेकिंग भी करते हैं। बुधवार को अपने आधिकारिक फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक संदेश में सद्गुरु ने कहा कि उनका एक कैलाश यात्रा समूह नेपाल लौटते समय अचानक आई बाढ़ में फंस गया था।

वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल रिजर्व पर अमेरिका का हुआ कंट्रोल, ट्रंप बोले– इतिहास की सबसे बड़ी डील

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अगस्त को वेनेजुएला के साथ दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका की कच्चे तेल तक पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और आखिर में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। ट्रंप ने कहा कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी के जरिए अमेरिका ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार पर ज्यादातर कंट्रोल हासिल कर लिया है।

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "मेरे कहने पर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो और सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर और प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी करके, वेनेजुएला में 65 अरब बैरल से ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार पर अमेरिका का ज्यादातर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके लिए अमेरिकी टैक्सपेयर की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।"

ट्रंप ने कहा कि ये समझौता अमेरिकी ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है और दावा किया कि इससे अमेरिकी तेल भंडार "दोगुने से भी ज्यादा" हो जाएंगे और पेट्रोल की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला ने डील का स्वागत किया। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के खजाने में भारी कमाई होगी। रोड्रिगेज ने कहा कि इस डील से वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा, खासकर तेल उद्योग को बढ़ाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और अपग्रेड करने में इनवेस्टमेंट होगा।

उन्होंने कहा, "ये समझौता प्राइवेट कंपनियों की मदद से तेल उत्पादन को बढ़ाएगा और इसमें 17 अहम तेल क्षेत्रों का विकास शामिल होगा, जिनमें लगभग 65 अरब बैरल का प्रमाणित भंडार है। इन प्रोजेक्ट्स से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का इनवेस्टमेंट आने और वेनेजुएला के लिए 209 अरब डॉलर से ज्यादा का टैक्स मिलने की उम्मीद है।

रोड्रिगेज ने कहा कि देश अपने विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक बनने, नौकरियां पैदा करने, कर्मचारियों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहता है। उन्होंने कहा, "इस तरह वेनेजुएला अपने लोगों के लिए रिकवरी, विकास, उत्पादन, सुरक्षा और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है।"

मौत के आंकड़ों पर चीन का झूठ! नेपाल में 600 से ज्यादा तो तिब्बत में कैसे सिर्फ 7 लोगों की गई जान?

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आई भयानक बाढ़ ने इस आपदा की दो बहुत अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर जहां नेपाल में पत्रकारों और बचे हुए लोगों ने तबाही के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, वहीं तिब्बत में जानकारी पर कड़ी पाबंदियों के कारण चीन की तरफ हुई तबाही का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है।

बाढ़ ने गांवों को तबाह कर दिया है, घरों को बहा ले गई है और सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। नेपाल पुलिस के मुताबिक, नेपाल में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 616 है। वहीं चीन ने तिब्बत में सिर्फ 7 लोगों की मौत की सूचना दी। इस बड़े अंतर ने बॉर्डर के चीनी हिस्से से आ रही जानकारी और आंकड़े पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सिर्फ 7 लोगों की मौत पर सवाल?

'द गार्डियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, तिब्बत की तरफ ग्यिरोंग बॉर्डर क्रॉसिंग के आस-पास के गांवों में हजारों लोग रहते हैं, फिर भी चीन में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 7 लोगों की मौत की जानकारी दी गई।

नेपाल में पत्रकार आपदा प्रभावित इलाके में बचे हुए लोगों, बचाव कर्मियों और स्थानीय निवासियों से बात करने के लिए पहुंचे। उनकी रिपोर्ट्स में विस्तार से बताया गया कि कैसे बाढ़ ने घरों को तहस-नहस कर दिया और लोगों व संपत्ति को बहा ले गई। हालांकि, वैज्ञानिक अभी भी बाढ़ के असली कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर के दूसरी तरफ तिब्बत में स्थिति कुछ साफ नजर नहीं आ रही है।

चीन की बाढ़ कवरेज पर भी सवाल

चीन के सरकारी मीडिया ने बाढ़ पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और प्रभावित इलाकों में पत्रकारों को भेजा है। हालांकि, ज्यादातर कवरेज तबाही के पैमाने के बजाय बचाव और राहत कार्यों पर केंद्रित रही है। तिब्बत में एक राहत केंद्र से प्रसारण के दौरान, चीनी पत्रकार ने अपने पीछे बैठे किसी भी शख्स से बात नहीं की। इस सीमित पहुंच की वजह से फ्रीलांसर और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है।

तिब्बत की कवरेज करना इतना मुश्किल क्यों है?

तिब्बत चीन के सबसे संवेदनशील और कड़े नियंत्रण वाले इलाकों में से एक है। इस इलाके में विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें ज्यादा फ्रीडम और धार्मिक आजादी की मांग करने वाले तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की घटनाएं भी शामिल हैं। चीनी अधिकारियों ने इन विरोध-प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया है। आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को तिब्बत से स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं होती है। वे वहां सिर्फ उन दौर के हिस्से के तौर पर जा सकते हैं जिन्हें आलोचक सरकार द्वारा आयोजित और कड़े नियंत्रण वाले दौरे बताते हैं।

CM सतीसन के काफिले को रोकने का आरोप, कांग्रेस नेता चेंथी अनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस नेता अनिल कुमार उर्फ चेंथी अनी को मुख्यमंत्री वी.डी। सतीसन के काफिले को रोकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अनी तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस समिति के नेता हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम चेम्पाझंथी में श्री नारायण गुरु जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, चेंथी में कार्यक्रम आयोजित कर रहे लोगों के एक समूह ने मुख्यमंत्री की गाड़ी को रुकने का इशारा किया। सीएम अनुरोध करने पर गाड़ी से उतरे। टेलीविजन फुटेज में उन्हें अनी के साथ बहस करते देखा गया। कुछ मिनट रुकने के बाद मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में लौट कर आगे बढ़ गए। पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम में चेंथी का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में अनी को हिरासत में लेकर श्रीकार्यम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तारी कर लिया गया। उन पर एफआईआर का मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 351(2) और 132 के तहत दर्ज किया गया है। ये धाराएं गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी और लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने से संबंधित हैं। एफआईआर के मुताबिक, शाम करीब 5:55 बजे मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकी। आरोप है कि उन्होंने आक्रामक अंदाज में पूछा कि तय कार्यक्रम होने के बावजूद वे क्यों नहीं आ रहे। जब आक्रामक व्यवहार न करने को कहा गया तो उसने धमकी दी, "अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम क्या कर लोगे?" एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने सबके सामने मुख्यमंत्री का अपमान किया।

नेपाल पर आफत, मजबूती से खड़ा रहे भारत... खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, की ये मांग

» **नेपाल को तत्काल मानवीय राहत सहायता देने का आग्रह**

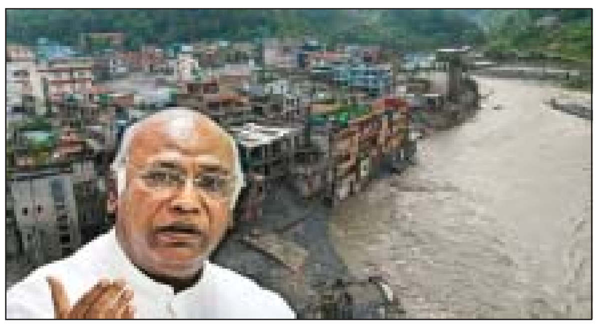

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पड़ोसी देश को तत्काल मानवीय एवं राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। उन्होंने 28 अगस्त को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा। खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि नेपाल में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है और हजारों लोग भोजन, दवाइयों, आश्रय तथा अन्य जरूरी सहायता की तत्काल जरूरत का सामना कर रहे हैं।

'भारतीयों की जल्द हो सुरक्षित वापसी'

खरगे ने सरकार से नेपाल के प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त मानवीय एवं राहत सहायता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर राहत एवं बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील भी की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, मैं नेपाल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को लेकर भी चिंतित हूं। संबंधित अधिकारियों को बचाव और निकासी के प्रयास तेज करने तथा उनकी सुरक्षित और जल्द भारत वापसी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, विदेश मंत्रालय से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार, करीब 320 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। गृह मंत्री शाह को लिखे पत्र में खरगे ने कहा, ये बड़े दुख के साथ लिख रहा हूं कि नेपाल हाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण उत्पन्न गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। जान-माल की क्षति, घरों और बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश तथा अनगिनत लोगों के विस्थापन ने प्रभावित समुदायों को अत्यंत संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा, भारत और नेपाल के लोगों के बीच गहरा एवं स्थायी संबंध है। इस गहरे दुख की घड़ी में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और इस विनाशकारी आपदा से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता देनी चाहिए।

'भारतीयों को मिले पूरा सहयोग'

खरगे ने नेपाल को तत्काल और व्यापक मानवीय तथा आपदा राहत सहायता देने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जहां भी आवश्यक हो और नेपाल सरकार के साथ समन्वय में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमों की तैनाती पर विचार किया जा सकता है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, निकासी और राहत अभियानों में सहायता की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में एनडीआरएफ की विशेषज्ञता और अनुभव लोगों की जान बचाने तथा संकट का सामना कर रहे लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। खरगे ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्रालय इस मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएगा तथा नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों तक भारत की सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करेगा।

प्रियंका की 'रीसेट' से इस एक्टर ने बनाई दूरी, शूटिंग से पहले लिया फैसला, फिल्म की फंडिंग में भी जुड़ा था नाम

प्रियंका चोपड़ा और ओरलैंडो ब्लूम की अपकमिंग फिल्म 'रीसेट' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्र्स के मुताबिक, ओरलैंडो ब्लूम ने शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही इस फिल्म से दूरी बना ली है।

TMZ की रिपोर्ट के अनुसार, ओरलैंडो ब्लूम इस सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्टिंग करने के साथ-साथ इसे को-प्रोड्यूस भी करने वाले थे। वह फिल्म के प्री-प्रोडक्शन के दौरान भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक, अब मेकर्स ओरलैंडो के किरदार के लिए तीन एक्टर्स पर विचार कर रहे हैं।

टीम जल्द ही इनमें से किसी एक को फाइनल कर सकती है, ताकि फिल्म की शूटिंग तय समय पर शुरू हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 'रीसेट' की फंडिंग और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में ओरलैंडो की मौजूदगी काफी अहम थी। फिल्म को प्रियंका और ओरलैंडो दोनों के प्रोजेक्ट से जुड़े होने के आधार पर सपोर्ट मिला था।

प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ओरलैंडो की जगह किस एक्टर को लिया जाएगा, इसका आखिरी फैसला प्रियंका ही करेंगी।

इन प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी प्रियंका

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।

वह जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं।

फिल्म में वह महेश बाबू के साथ नजर आएंगी। इसमें ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावाणी का संगीत है।

फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इसके अलावा प्रियंका प्राइम वीडियो की 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन में एक बार फिर नादिया सिंह के किरदार में नजर आएंगी।

वह हॉलीवुड स्टार रसेल क्रो के साथ साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'ब्लूफ्लाई' में भी दिखाई देंगी।

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का गाना 'कहो तो' हुआ रिलीज, अरमान मलिक की आवाज का फिर चलेगा जादू?

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का नया रोमांटिक गाना 'कहो तो' मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस गाने में अरमान मलिक की सुरीली आवाज फैंस को फिर सुनने मिल रही हैं।

वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का दूसरा गाना 'कहो तो' रिलीज हो चुका है। फिल्म कॉलेज लाइफ पर आधारित है और उसी दौरान होने वाले रोमांस पर आधारित है। मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना 'कहो तो' रिलीज किया है।

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' में वीर पहाड़िया को दर्शक एक रोमांटिक अंदाज में देखने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ आफिया सैयद भी नजर आने वाली हैं। कैसा है यह गाना?

अमाल ने एक्स पर आपनी वापसी की जानकारी देते हुए एक पोस्ट में लिखा, 'मैं बिल्कुल ठीक हूं और इस बार मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। वही करूंगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है और सिर्फ वही करूंगा जो मेरे दिल और मेरी सेहत के लिए जरूरी है। अपने मन, शरीर, आत्मा और पूरी तरह से ठीक होने के लिए एक ब्रेक चाहिए। उठने, ठीक होने और जल्द ही आप सभी प्यारे अमालियंस के लिए धुनों से भरे दिल के साथ वापस आने की जरूरत है।

कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था। इसकी जानकारी वीर पहाड़िया ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा, 'दोस्ती के किस्से हो या प्यार के लफड़े। लाइफ इनके बिना अधूरी है।' इसके साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी जिक्र किया है। यह फिल्म इस साल गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्तूबर 2026 को रिलीज होगी।

जाने वाले को बिग बॉस रोक सकता है...सलमान खान ने खोला 'एक्स्ट्रा जीवनदान' का सबसे बड़ा राज!

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में इस बार एलिमिनेशन का नियम पूरी तरह बदल गया है। बेघर होने वाले कंटेस्टेंट्स को 'वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवनदान' मिलेगा और वो घर के अंदर ही रहेंगे।

भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित, विवादित और बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' एक बार फिर दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शो के होस्ट और बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान ने नए सीजन के ग्रैंड प्रीमियर से ठीक पहले एक ऐसा धमाका कर दिया है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। पिछले 19 सीजनों में जो नियम पत्थर की लकीर माने जाते थे, मेकर्स ने इस बार उस खेल को ही पूरी तरह पलट दिया है। इस 20वें सीजन में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट शो के एलिमिनेशन प्रोसेस में देखने को मिलने वाला है।

जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किए गए नए प्रोमो में सलमान खान अपने दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान खान कहते दिखते हैं,"लोग कहते हैं न जाने वाले को कौन रोक सकता है... बिग बॉस रोक सकता है। इस बार घर से जो एलिमिनेट होगा, वो घर में ही रहेगा, क्योंकि सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवनदान।

तथास्तु मेरी जान!"

प्रोमो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। कैप्शन में मेकर्स ने साफ लिखा है, 'डबल द चांस... ट्रिपल द ड्रामा... तथास्तु मेरी जान'। यानी इस बार अगर कोई कंटेस्टेंट वोट्स की कमी या नॉमिनेशन के चलते बेघर भी घोषित होता है, तो वह सीधे मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाएगा। मेकर्स ने इस बार खिलाड़ियों को घर के अंदर ही रखकर 'दूसरा मौका' या किसी सीक्रेट रूम/पैरेलल स्पेस के जरिए खेल में बनाए रखने का नया चक्रव्यूह रचा है।

डबल ड्रामा और माइंड गेम्स की तैयारी

आमतौर पर हर हफ्ते बेघर होने के डर से कंटेस्टेंट्स अपनी रणनीतियां बदलते हैं, लेकिन 'एक्स्ट्रा जीवनदान' के इस वरदान ने खेल के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। जो खिलाड़ी एलिमिनेट होकर भी घर के अंदर मौजूद रहेंगे, वो बाकी घरवालों के असली चेहरों और उनकी पीठ पीछे की जासूसी का पर्दाफाश कर सकेंगे।

फिलहाल घर में एंट्री लेने वाले कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एलिमिनेशन के इस मास्टरस्ट्रोक ने यह साफ कर दिया है कि 'बिग बॉस 20' में ड्रामा, कलेश और एंटरटेनमेंट पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com